हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के बीच नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार समेत सोमवार की रात चंडीगढ़ पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के परिवार के साथ रात्रि भोज किया।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

एक्शन इंडिया

वर्ष: 15 अंक: 168 पृष्ठ: 08 RNI : HPHIN/2012/48072

actionindiauna@gmail.com | हिमाचल संस्करण | दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड - चंडीगढ़

RKB GROUP Rakesh Bhardwaj Group

फास्ट न्यूज

लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते तथा कच्चे तेल की कीमत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई गिरावट से उत्साहित शेयर बाजार आज लगातार तीसरे कारोबारी दिन मजबूती के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत भी मजबूती के साथ हुई थी। दिन के पहले सत्र के दौरान बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहा, लेकिन दूसरे सत्र में खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया। लिवाली के सपोर्ट से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक अच्छी बढ़त हासिल करने में सफल रहे। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.71 प्रतिशत और निफ्टी 0.57 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एनर्जी और मीडिया सेक्टर के शेयरों में लगातार खरीदारी होती रही। इसी तरह एफएमसीजी, रियल्टी, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और टेक इंडेक्स भी मजबूती के साथ हरे निशान में बंद हुए। दूसरी ओर, मेटल, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में आज लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी आज खरीदारी होती रही, जिसके कारण निफ्टी का मिडकैप इंडेक्स 0.41 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ आज के कारोबार का अंत किया।

देश के 23 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में जनगणना का पहला चरण पूरा

नई दिल्ली। जनगणना-2027 के तहत मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना (एचएलओ) का पहला चरण अब तक 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में जनगणना का कार्य चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया

जी7 सम्मेलन में पीएम ने की ट्रम्प सहित विश्व नेताओं से मुलाकात

सम्मेलन

पीएम मोदी और ट्रम्प की फ्रांस के एवियन शहर में जी7 समिट के दौरान मुलाकात हुई

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे विभिन्न देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की तथा समृद्धि, सतत विकास और मानव कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से भी मुलाकात हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर जी7 नेताओं और विशेष आमंत्रित नेताओं की सामूहिक तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वें जी7 शिखर सम्मेलन में पारिवारिक तस्वीर खिंचवाने के लिए एकत्रित हुए। यह वैश्विक चुनौतियों से निपटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। नीस में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंच पर भी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया। वहीं पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की फ्रांस के एवियन शहर में जी7 समिट के दौरान मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात की। मीटिंग में दोनों एक-साथ बैठे नजर आए। यह मुलाकात 16 महीनों के बाद हुई है। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जी7 आउटरीच सेशन में भी साथ-साथ बैठे। इससे पहले आखिरी मुलाकात फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी। दोनों नेता 17 जून की शाम 6:30 बजे ट्रेड डील पर चर्चा कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ, निवेश और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जी7 समिट के लिए मंगलवार दोपहर एवियन पहुंचने पर मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्वागत किया। जी7 के देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। भारत और फ्रांस ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने तथा अधिक समृद्ध, सतत और समावेशी भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि एवियन पहुंचकर उन्हें विश्व नेताओं के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि जी-7 देशों के नेताओं के साथ चर्चा हमेशा उपयोगी रहती है और भारत एक अधिक सतत तथा समृद्ध विश्व के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जी7 समिट में 12 देशों के नेता हिस्सा ले रहे

जी7 समिट में इसके सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल होंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। फ्रांस ने समिट में जी7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज, नासियो लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यंग, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो भी शामिल हैं।

जी7 क्या है, इसमें कौन-कौन से देश हैं?

जी7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन, दुनिया के उन 7 देशों का समूह है, जिन्हें दुनिया की 'मॉडर्न इकोनॉमी' वाला देश कहा जाता है। इनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी शामिल हैं। इसकी शुरुआत 1975 में जी76 के रूप में हुई थी। 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद यह जी7 बन गया। 1998 में रूस को शामिल कर इसका नाम जी8 कर दिया गया, लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर रूस के कब्जे के बाद उसे समूह से बाहर कर दिया गया।

भारत जी7 में गेस्ट नेशन, पीएम 7वीं बार शामिल होंगे

भारत जी7 का सदस्य नहीं है, लेकिन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका के कारण उसे अक्सर विशेष आमंत्रित देश है।

दिल्ली की झुग्गियों के पुनर्वास व पुनर्स्थापन पर अमित शाह ने की उच्चस्तरीय बैठक: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

अवैध लिंग जांच पर हरियाणा का सख्त कदम

टीम एक्शन इंडिया

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अवैध लिंग जांच के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब उत्तर प्रदेश का सहयोग लेने का फैसला किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश के साथ सहयोग की पहल की है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) अमित कुमार घोष को लिखे पत्र में डॉ. मिश्रा ने जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार तथा हाबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओह अभियान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रति दोनों राज्यों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। राज्य की टीमें अवैध लिंग जांच में संलिप्त तत्वों के खिलाफ लगातार डिकॉय ऑपरेशन और छापेमारी कर रही हैं।

दिल्ली-एनसीआर में चार नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाएंगे : मनोहर लाल

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में चार नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाएंगे और दिल्ली के आसपास एक आधुनिक सब-सिटी 'नमो सिटी' बनाई जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी) की 42वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में एनसीआर के विकास, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मनोहर लाल ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि रीजनल प्लान 2041 को अगले दो महीनों में अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जाएगा। एनसीआर की मौजूदा सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। योजना के तहत हर राज्य में एक बड़ा शहर ग्रीनफील्ड 'नमो नोड' के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली के आसपास बनने वाली 'नमो सिटी' को अत्याधुनिक शहरी सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे से लैस किया जाएगा।

हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों को राहत, नई तबादला नीति तक आपसी सहमति से मिलेगा स्थानांतरण का अवसर

टीम एक्शन इंडिया

चंडीगढ़: हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा नई स्थानांतरण नीति लागू किए जाने तक रोडवेज कर्मचारियों को आपसी सहमति के आधार पर एक बार स्थानांतरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकताओं का समाधान होगा तथा विभिन्न डिपो में कार्यबल की उपलब्धता और कार्य क्षमता भी प्रभावित नहीं होगी। विज ने मंगलवार को चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन तथा हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुचित व्यवस्था, वाटर कूलर तथा महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

अल नीनो से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय ने तैयार की रणनीति

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कृषि भवन में उच्चस्तरीय बैठक कर संभावित अल नीनो परिस्थितियों से निपटने की रणनीति की समीक्षा की। उन्होंने कपास का उत्पादन बढ़ाने, दलहन में आत्मनिर्भरता और कम बारिश वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजना पर विशेष जोर दिया। बैठक में अल नीनो की संभावित स्थिति पर चर्चा करते हुए

शिवराज सिंह चौहान ने साफ निर्देश दिया कि जिन जिलों में कम बारिश या वर्षा में असमानता की आशंका है, वहां पहले से पूरी तैयारी की जाए। ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान कर राज्य सरकारों के साथ मिलकर फसलवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार किए जाएं, ताकि किसी भी मौसमी चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने

इंटरक्रॉपिंग

पानी के संरक्षण, नमी प्रबंधन, इंटरक्रॉपिंग और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दें

कहा कि पानी के संरक्षण, नमी प्रबंधन, इंटरक्रॉपिंग और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान देते हुए हर जोखिम वाले जिले के लिए अलग और व्यावहारिक रणनीति बनाई जाए। चौहान ने यह भी निर्देश दिए कि जिन 9-10 राज्यों में अल नीनो का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ सकता है, वहां के चिह्नित जिलों के जिला अधिकारियों, कृषि विभाग, केवीके और अन्य विस्तार तंत्र के साथ समन्वित बैठकें आयोजित की जाएं।

नीट-पेपर लीक पर संग्रामः खरगे ने टेलीग्राम बैन पर सरकार को घेरा

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न मांगकर मोदी सरकार जवाबदेही की पहली परीक्षा में ही पूरी तरह फेल हो चुकी है। खरगे ने आगामी 21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुनर्परीक्षा से ठीक पहले सरकार की ओर से मैसेजिंग एप टेलीग्राम पर लगाए गए प्रतिबंधों की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार टेलीग्राम ब्लॉक करने के बजाय शिक्षा मंत्री को पद से हटाए, जिन्होंने देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य ही ब्लॉक कर दिया है।

आठ वर्ष पुराना वित्तीय विवाद सुलझाः मुख्यमंत्री, परियोजना के विद्युत घटक पर होने वाली 2,000 करोड़ रुपये की लागत लाभान्वित राज्य करेंगे वहन

किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल को मिली बड़ी सफलता

परियोजना

परियोजना के पूरा होने के बाद हिमाचल को हर वर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी

टीम एक्शन इंडिया
पंकज शर्मा

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने किशाऊ बांध परियोजना में प्रदेश के हितों की रक्षा करते हुए एक और मील पत्थर हासिल किया है। मुख्यमंत्री के सतत प्रयासों से लगभग 15,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित होने

वाली 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना टौंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रस्तावित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश हित की मजबूती से पैरवी की और पिछले आठ वर्षों से परियोजना को वित्तीय लागत वहन करने से संबंधित गतिरोध को समाप्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। भारत सरकार ने परियोजना के जल घटक के रूप में लाभान्वित होने वाले राज्यों दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा द्वारा हिमाचल प्रदेश के हिस्से के विद्युत घटक के रूप में होने वाली लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का वहन करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के दृढ़ प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश को होने वाला वित्तीय बोझ कम होगा, जबकि पूर्व की सरकार ऐसा करने में सफल नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने राज्य के हिस्से के रूप में 800 करोड़ रुपये प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने प्रदेश के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश हित में इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि परियोजना के जल घटक के लिए भारत सरकार 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवा रही है, इस स्थिति में विद्युत घटक के लिए इसी प्रकार की सहायता न मिलना अनुचित था। इस परियोजना के कारण विस्थापन का सबसे अधिक प्रभाव हिमाचल प्रदेश की आबादी पर पड़ेगा और राज्य को इससे अधिक नुकसान होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना न्यायसंगत नहीं था तथा राष्ट्र निर्माण में हिमाचल प्रदेश के योगदान की उचित प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त राज्य को विद्युत घटक के रूप में प्रतिवर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 600 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होगी। इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी।

आईएसआई समर्थित आतंकी-क्राइम मॉड्यूल का भंडाफोड़, सात गिरफ्तार

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के समर्थन से संचालित एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी-आपराधिक नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुज्जर के इशारे पर संचालित हो रहा था। यह नेटवर्क पंजाब के रास्ते ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार, कारतूस और मादक पदार्थ मंगाकर दिल्ली-एनसीआर में उनकी सप्लाई करता था। पुलिस का दावा है कि समय

रहते कार्रवाई कर दिल्ली-एनसीआर में कई संभावित आतंकी घटनाओं को टाल दिया गया। पुलिस उपायुक्त नारा चैतन्य ने मंगलवार को बताया कि स्पेशल सेल की पूर्वी रेंज को मई 2026 के मध्य में खुफिया जानकारी मिली थी कि शहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल कर दिल्ली-एनसीआर में हमलों की साजिश रच रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले गाजियाबाद के लोनी निवासी मोहित उर्फ योगी (26) को दिल्ली के यमुना विहार स्थित भागीरथ जल शोधन संयंत्र के पास से दबोचा। उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और अजमल गुज्जर से जुड़े चैट और वॉइस नोट वाला मोबाइल फोन बरामद किया गया। मोहित से पूछताछ के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। उसकी निशानदेही और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने अनस उर्फ अनस त्यागी, दीपक उर्फ दीपक अहीला, आरिफ उर्फ प्रधान, करणवीर सिंह, जतन और साबिर को गिरफ्तार किया।

उत्तर भारत
ACTION INDIA
ऊना, 17 जून 2026
दैनिक एक्शन इंडिया
http:// www.actionindialive.com

बेहतर प्रबंधन और कुशलता के साथ संपन्न कराएं नीट परीक्षा: मोहन

नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। इसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। बेहतर प्रबंधन एवं कार्य कुशलता से पूरी पारदर्शिता के साथ यह परीक्षा सम्पन्न कराएं: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

टीम एक्शन इंडिया

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीट पुनर्परीक्षा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। इसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। बेहतर प्रबंधन एवं कार्य कुशलता से पूरी पारदर्शिता के साथ यह परीक्षा सम्पन्न कराएं। परीक्षा के आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को मंत्रालय में नीट (अंडर ग्रेजुएट) परीक्षा-2026 की तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की।यह परीक्षा 21 जून को होने जा रही है। यह परीक्षा मध्य प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों में सम्पन्न कराई जाएगी। नीट परीक्षा की कुल अवधि 'सवा तीन घंटे' की होगी। इस बार सभी परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने नीट परीक्षा के समन्वयक को निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षा केन्द्रों में लगाई जाने वाली बायोमैट्रिक मशीन, सीसीटीवी कैमरे एवं जैमर 19 जून को ही परीक्षा केन्द्रों में लगा दिए जाएं और 20 जून को इनका ट्रायल रन भी कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का जबलपुर प्रवास प्रस्तावित है। जबलपुर शहर में 24 केंद्रों में नीट परीक्षा होनी है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी यातायात का ऐसा प्रबंधन करें कि सभी परीक्षार्थी बिना किसी बाधा के अपने-अपने परीक्षा केंद्रों में सुगमता से पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि चूंकि नीट परीक्षा के दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन भी होने हैं। इन आयोजनों के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। यातायात का बेहतर नियोजन करें। सुनिश्चित करें कि सभी परीक्षार्थी तय समय से पहले तक केन्द्रों में पहुंच जाएं। किसी परीक्षार्थी को यदि सेंटर तक पहुंचने में आवागमन के साधन की परेशानी आ रही है तो प्रशासन और पुलिस अधिकारी किसी शासकीय वाहन या खुद अपने वाहन से उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परीक्षा केंद्रों वाले सभी 30 जिलों के कलेक्टर-एसपी एवं परीक्षा सम्पन्न कराने की व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि नीट परीक्षा की तैयारियों के लिए उपयोग में लाई गई एसओपी अब प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपयोग में लाई जाएगी। परीक्षा केन्द्रों वाले जिलों के पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर परीक्षा की अब तक की तैयारियों की जानकारी दी। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने परीक्षा की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि नीट परीक्षा आयोजन के लिए जिलास्तरीय समन्वय समिति का गठन कर इनकी बैठकें भी कर ली गई हैं।

प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक क्लॉक रूम भी होगा

परीक्षा केंद्रों में सभी विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, ओआरएस और ग्लूकोज की व्यवस्था, प्रत्येक केंद्र पर एक प्राथमिक स्वास्थ्यकर्मी एवं प्राथमिक उपचार किट, नियंत्रण कक्ष में डॉक्टरों और पैरामेडिकल की स्वास्थ्य टीम भी रहेगी, जिनका रिस्पांस टाइम न्यूनतम रहेगा। परीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों के साथ आने वाले परिजनों/अभिभावकों/संरक्षकों के लिए पर्याप्त आकार का टेंट और मोबाइल शौचालय बनाए जाएंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक क्लॉक रूम भी होगा। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए समुचित तरीके से भीड़ प्रबंधन किया जायेगा, साथ ही शहर से दूर स्थापित परीक्षा केंद्र तक विद्यार्थियों को पहुंचाने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इन जिलों में होगी नीट की परीक्षानीट (अंडर ग्रेजुएट) परीक्षा – 2026 मध्य प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केन्द्रों में होगी। यह परीक्षा इन्दौर, बड़वानी, खरगौन, धार, खंडवा, नर्मदापुरम्, मुरैना, नीमच, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा और सतना जिले में होगी।

प्रत्येक 3-4 परीक्षा केन्द्रों के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति

नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर जिला नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। प्रत्येक 3–4 परीक्षा केन्द्रों के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सहायक उपनिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

राजन ने बताया कि नीट परीक्षा आयोजन के लिए संबंधित जिलों में सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये गये हैं। परीक्षा के प्रश्नपत्र प्रदेश के 5 एयरपोर्ट के जरिए पहुंच चुके हैं। प्रश्न पत्र दो अधिसूचित बैंकों में सुरक्षित रखे गये हैं। परीक्षा के दिन वाहनों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। इन वाहनों की जानकारी शाम तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में द्वि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बाहरी सुरक्षा परत राज्य पुलिस/होमगार्ड की होगी। आंतरिक सुरक्षा परत एनटीए द्वारा नियुक्त एजेंसी की रहेगी। महिला विद्यार्थियों के लिए अलग से फ्रिस्किंग सुविधा रहेगी। इसके लिए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। परीक्षा कक्ष में उचित प्रकाश व्यवस्था तथा पंखे चालू अवस्था में हों, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

महिला सशक्तीकरण का डबल इंजन मॉडल: महिला सुरक्षा, सम्मान एवं अवसरों का वातावरण

टीम एक्शन इंडिया

लखनऊः वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने और वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद प्रदेश में विकास की नई धारा देखने को मिली। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा लाभ यदि किसी वर्ग को मिला है तो वह प्रदेश की महिलाएं हैं। केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित नीतियों ने महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा है। केंद्र की योजनाओं और राज्य सरकार के प्रभावी क्रियान्वयन ने लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है।

प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और अवसरों का वातावरण

आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और अवसरों का वातावरण पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत दिखाई देता है। उज्ज्वला योजना, मिशन शक्ति, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी, कन्या सुमंगला योजना जैसी पहलों ने महिलाओं को न केवल सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान किया है।

> सुरक्षित बेटी, सशक्त महिला एवं आर्थिक सशक्तीकरण का मॉडल बना उत्तर प्रदेश

महिलाओं की सुरक्षा है योगी सरकर की प्राथमिकता

महिला सशक्तीकरण की पहली शर्त सुरक्षा है, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण नहीं मिलेगा तो शिक्षा, रोजगार और स्वावलंबन के अवसर भी सीमित रह जाएंगे। योगी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया, महिला हेल्पलाइन 1090 को मजबूत किया गया, महिला डेस्क की स्थापना की गई तथा मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता पैदा की गई। महिला सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस भर्ती में महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 44 हजार से अधिक हो गई, जबकि वर्ष 2017 तक यह संख्या लगभग 10 हजार के आसपास थी। महिलाओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और संवेदनशील मामलों में बेहतर पुलिसिंग को सुनिश्चित किया है।

आज प्रदेश के लगभग हर जिले

मोदी सरकार ने नक्सलिज्म और जिहादी टेररिज्म से देश को मुक्ति दिलाई : तेजस्वी

टीम एक्शन इंडिया

जोधपुरः भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने पर कहा कि पहली बार भारत के इतिहास में किसी सरकार ने शानदार काम किया है तो वह मोदी सरकार है। विशेषकर नक्सलिज्म और जिहादी टेररिज्म से देश को मुक्त किया है। एयरपोर्ट पर मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मोबाइल फोन निर्माण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक दशक पहले अधिकांश मोबाइल विदेशों से आयात किए जाते थे, जबकि आज भारत में बड़े पैमाने पर उनका निर्माण और असेंबलिंग हो रही है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य-पूर्व में तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पचरुखी प्रखंड के पपौर पंचायत में आयोजित 'सबका सम्मान, जीवन आसान' सहयोग शिविर में हिस्सा लेते हुए जिले को 415 .18 करोड़ रुपये की 44 विकास योजनाओं की सौगात दी।

आस्था स्थलों के विकास को सरकार ने दी रफ्तार, 33 परियोजनाओं पर शुरू हुआ काम

टीम एक्शन इंडिया

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में पर्यटन विभाग ने 31 मार्च 2026 तक स्वीकृत परियोजनाओं पर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के 8 जिलों में 33 पर्यटन एवं धार्मिक विकास परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है, जिन पर लगभग 79.18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता ह्यआस्था के साथ विकासह्व है। इसी सोच के तहत धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों का सौंदर्यीकरण कर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर टेंपल इकोनॉमी को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है। स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि जारी कर दी गई है और कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

टीवीएस रेडर ने स्टाइल आइकन अवॉर्ड्स 2026 के साथ की साझेदारी

टीम एक्शन इंडिया

मंडीः नई पीढ़ी के राइडरों के लिए भारत की स्टाइलिश मोटरसाइकल टीवीएस रेडर ने टाइटल पार्टनर के रूप में स्टाइल आइकन अवॉर्ड्स 2026 के साथ साझेदारी की है। यह भारत के युवा एवं स्टाइल के प्रति सजग उपभोक्ताओं के साथ ब्राण्ड के जुड़ाव को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह साझेदारी मोबिलिटी,फैशन, एंटरटेनमेन्ट और मशहूर संस्कृति की दुनिया को एक साथ लाकर टीवीएस रेडर की स्थिति को और मजबूत बनाती है जो आज के युवाओं की पहचान एवं महत्वाकांक्षाओं के साथ मेल खाती है। अपने खास डिजाइन,परफोर्मेन्स एवं युवाओं को लुभाने वाले अंदाज के लिए मशहूर टीवीएस रेडर ऐसी पीढ़ी के साथ जुड़ी रही है जो स्व अभिव्यक्ति और प्रमाणिकता को महत्व देते हैं। भारत के अग्रणी स्टाइल प्लेटफॉर्म्स में से एक के साथ एसोसिएशन के द्वारा ब्राण्ड ने उन दर्शकों के साथ जुड़ने का लक्ष्य रखा है जिनके लिए स्टाइल फैशन के दायरे से बढ़कर रोजमर्रा के पसंदीदा विकल्पों तक जाता है।

मप्र सबसे पहले हुआ नक्सलमुक्त: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

टीम एक्शन इंडिया

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही नक्सलवाद को समाप्त किया है। लाल सलाम को आखिरी सलाम करने में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 जून को नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के विकास के हर मामले में सदैव अग्रणी रहने की क्रियाशीलता की सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक से पहले मंत्रीगण से अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय "विकसित भारत @2047 के लिये समावेशी मानव विकास" था। पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की शासी परिषद् की बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझी भागीदारी, समन्वित प्रयासों तथा विकास के विभिन्न आयामों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हुई। देश के जो क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित थे, वहां विकास की गति तेज करने पर चर्चा हुई। भविष्य में युवाओं के विकास पर सरकार का विशेष रूप से जोर रहेगा।

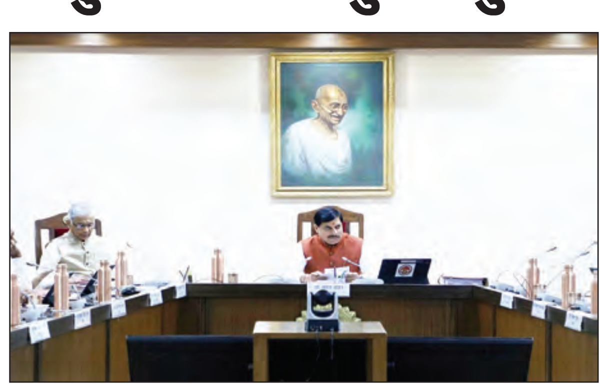

अलीगढ़ की वन्दना सिंह बनीं प्रदेश टॉपर

उत्तर प्रदेश संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा-2026 का परिणाम घोषित

टीम एक्शन इंडिया

लखनऊः मंगलवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के पुस्तकालय भवन में उत्तर प्रदेश संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा-2026 का परिणाम घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा-2026 के टॉपर्स से उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्यमंत्री रजनी तिवारी, कुलपतिगण तथा प्रमुख सचिव एवं सचिव द्वारा वीडियो कॉल पर वार्ता कर शुभकामनाएं दी और उनकी भविष्य की योजनाओं को जाना। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अभ्यर्थियों ने अपने भविष्य की दिशा तय की है। उन्होंने कहा कि माता-पिता के त्याग और गुरुओं के मार्गदर्शन से ही यह मुकाम हासिल हुआ है। 'गुरु देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव' की भावना के साथ हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। देशभक्ति केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। समाज ने जो जिम्मेदारी दी है, उसका ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण से पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है।

उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने टेक्नोलॉजी और एआई को जोड़कर अभेद्य सिस्टम से परीक्षा कराई। यह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि परीक्षाएं कैसे शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता के साथ कराई जाएं। योगी सरकार के आने के बाद लखनऊ, बरेली और अब झांसी विश्वविद्यालय ने बी.एड. परीक्षाएं कराकर शिक्षा के स्तर को सुधारा है। पहले नकल को बढ़ावा देने की बात होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी से जुड़कर परीक्षाएं नकलविहीन हो रही हैं। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि आज बी.एड. करने वाले छात्रों के लिए हर्ष का दिन है।

गो संरक्षण विशेष: प्रदेश के हर जिले में विकसित होगा एक प्रमुख गो आधारित उद्योग

टीम एक्शन इंडिया

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग ने गोशालाओं की क्षमता का राज्यव्यापी मूल्यांकन पूरा कर लिया है। इसके आधार पर अब प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थानीय संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप एक प्रमुख गो आधारित उद्योग विकसित करने की तैयारी है। इस पहल को "एक जनपद-एक नवाचार" मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा।

गोशालाओं की भूमि, गोवंश, जल

> सीएम की मंशा के अनुरूप स्थानीय स्तर पर विकसित होंगे छोटे उद्योग, ग्रामीण युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार के मिलेंगे अवसर

संसाधन और स्थानीय बाजार के आधार पर आकलन

योजना का उद्देश्य गोशालाओं को केवल निराश्रित गोवंश के संरक्षण तक सीमित न रखकर उन्हें उत्पादन, रोजगार, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण उद्यमिता के केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसके लिए प्रदेशभर की गोशालाओं में उपलब्ध भूमि, गोवंश, जल संसाधन, पंचगव्य इकाइयों और स्थानीय बाजार की संभावनाओं का विस्तृत आकलन किया गया है।

किसी जिले में बायोगैस उत्पादन तो कहीं इको पेंट निर्माण को मिलेगा बढ़ावा

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि निरीक्षण और अध्ययन के बाद प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग नवाचार मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। किसी जिले में बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा तो कहीं इको पेंट निर्माण, जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट, गोबर आधारित उत्पाद, पंचगव्य उत्पादों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर छोटी उद्योग इकाइयों का विकास होगा और ग्रामीण युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

जिला विशेष नवाचार मॉडल के माध्यम से संसाधनों को आय और रोजगार में बदलने की रणनीति तैयार की गई है। योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से जोड़ा जाएगा। यह मॉडल सफल होने पर गोशालाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, प्राकृतिक खेती को नई गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। साथ ही प्रत्येक जिले की एक विशिष्ट गो-आधारित पहचान विकसित होगी, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगी।

शिमला पुलिस का बड़ा एक्शन, 316 ग्राम चिट्टा बरामद, पंजाब से सप्लायर गिरफ्तार

दबिश

» तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर थाना सदर, शिमला टीम ने खरड़ में दी दबिश

चमन शर्मा

शिमला। शिमला पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चिट्टे की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने की दिशा में अहम सफलता हासिल की है। थाना सदर पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज जांच के आधार पर पंजाब के खरड़ से एक बड़े सप्लायर को गिरफ्तार किया है।

मामले में अब तक कुल 316 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है। एएसपी शिमला हेडक्वार्टर अभिषेक ने बताया कि शिमला पुलिस द्वारा चिट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान के तहत थाना सदर में 10 जून 2026 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में मंडी जिला के धर्मपुर निवासी राहुल ठाकुर के कब्जे से करीब 7 ग्राम चिट्टा और 23 हजार रुपये नकद बरामद किए गए थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों, व्हाट्सएप चैट और वित्तीय लेन-देन का गहन विश्लेषण किया।

जांच में खुलासा हुआ कि बरामद चिट्टे की सप्लाई पंजाब के खरड़ निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ हैरी द्वारा की गई थी, जो लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय था। उन्होंने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर थाना सदर, शिमला की पुलिस टीम ने 13 जून को खरड़ में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 309 ग्राम चिट्टा और 61,900 रुपये नकद बरामद किए गए।

इस तरह मामले में कुल 316 ग्राम हेरोइन बरामद हो चुकी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों और तस्करों से संपर्क करता था। वह भुगतान अपने बैंक खाते में लेने के बजाय दोस्तों और परिवार के सदस्यों के खातों में मंगवाता था और तुरंत नकदी निकालकर अपने पास रख लेता था, ताकि जांच एजेंसियों से बचा जा सके। शिमला पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है और सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है।

दो पिकअप ट्रालों में ठूंस-ठूंसकर ले जाई जा रही 10 भैंसें पकड़ीं

राजन पुरी

ऊना। थाना बंगाणा के तहत हरीनगर में पुलिस ने पशु क्रूरता के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो पिकअप ट्रालों में क्षमता से अधिक संख्या में भैंसों को ठूंस-ठूंसकर ले जा रहे दो व्यक्तियों को काबू किया है। पुलिसि ने दोनों वाहनों सहित 10 भैंसों को कब्जे में चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार पुलिस थाना बंगाणा की टीम सोमवार देर रात हरिनगर क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बंगाणा की ओर से ऊना की तरफ आ रहे दो पिकअप ट्रालों पर पुलिस की नजर पड़ी। संदेह के आधार पर दोनों वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। जांच के दौरान पहले पिकअप में चार भैंसें और दूसरे में छह भैंसें भरी हुई पाई गईं।

15 करोड़ की पेयजल योजना से बदलेगी लाठियाणी जिला वार्ड की तस्वीर: विवेक

निरीक्षण

» विधायक ने तुरकाल पेयजल योजना के कार्य का किया निरीक्षण

राजन पुरी

ऊना। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की बुधान ग्राम पंचायत के तुरकाल में करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से बन रही महत्वाकांक्षी पेयजल योजना का कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए अधिकारियों से पेयजल योजना की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त भी की। विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि यह पेयजल योजना लाठियाणी जिला पार्षद वार्ड की सभी पंचायतों के लिए वरदान साबित होगी और क्षेत्र में पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

निरीक्षण के दौरान जल शक्ति विभाग मंडल थानाकला के अधिशाषी अभियंता हरभजन सिंह ने विधायक विवेक शर्मा को योजना की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है तथा पौने दो माह के भीतर योजना का लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। विधायक विवेक शर्मा ने निर्माण कार्य की गति पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र के लाठियाणी वार्ड के लोगों की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित होगी। शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सहयोग और जल शक्ति विभाग की तत्परता से इस योजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

ननावीं में बाइक ने स्कूटी को मारी टक्कर, दंपती घायल

राजन पुरी

ऊना। थाना बंगाणा के तहत ननावीं गांव में बाइक की टक्कर से स्कूटी सवार दंपती के घायल होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को दी शिकायत में दिनेश कुमार निवासी ननावीं ने बताया कि वह निजी बस में परिचालक के पद पर कार्यरत हैं। बीते शनिवार शाम अपनी स्कूटी पर पत्नी कुसम लता के साथ लठियाणी की ओर जा रहे थे। जब वे ननावीं में पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार आ रहे एक मोटरसाइकिल चालक ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के कारण दिनेश कुमार और उनकी पत्नी सड़क पर गिर गए।

जन समस्याओं का समाधान तीव्रता से करें अधिकारी : रोहित ठाकुर

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां बचत भवन में आयोजित की गई।

शिक्षा मंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जन शिकायत निवारण समिति में सामाजिक मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाया गया। विभागों ने इन मुद्दों के समाधान को लेकर मौजूदा स्थिति एवं रणनीति के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी रखी। आपदा के कारण जिला शिमला में वर्ष 2023 और 2025 में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। प्रदेश सरकार ने प्रभावितों के लिए हर संभव सहायता मुहैया करवाई है। सड़कों, पेयजल योजनाओं, घरों आदि काफी क्षतिग्रस्त हुए थे। लेकिन सरकार के विशेष आपदा राहत पैकेज की वजह से अब स्थितियां सामान्य हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आरडीजी बंद होने से सरकार को वित्तीय घाटा हो रहा है परन्तु सरकार जनकल्याण हेतु प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन बैठक में रखे गए मुददों के समाधान के लिए धरातल पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जन समस्याओं के समाधान के लिए तीव्रता से कार्य करें ताकि जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि दुनिया में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है। इस वजह से जिला शिमला में बागबानी क्षेत्र से जुड़े बागवानों को भी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। सड़कों में टारिंग के लिए भी डीजल की किल्लत से परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। प्रशाासन पेट्रोल डीजल की प्रयाप्त पूर्ति के लिए कार्य करें।

19 जून की रात 11:30 बजे से 21 जून दोपहर 4 बजे तक छोड़ा जाएगा चमेरा-।।। जलाशय का पानी

हामिद खान

चंबा। चमेरा-।।। पावर स्टेशन, खड़ामुख के महाप्रबंधक (विद्युत) टिकेश्वर प्रसाद ने बताया कि चमेरा-।।। बांध के खड़ामुख स्थित

जलाशय से 19 जून की रात 11:30 बजे से 21 जून की दोपहर लगभग 4 बजे तक पानी छोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान बांध के गेट खोलकर जलाशय का पानी चरणबद्ध और नियंत्रित तरीके से छोड़ा जाएगा, ताकि नदी में प्राकृतिक (फ्री) फ्लो बहाल हो सके। पानी छोड़े जाने के कारण बांध के निचले क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है।

महाप्रबंधक ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनज़र पानी छोड़े जाने से पहले सायरन और हूटर बजाकर लोगों को सतर्क किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के प्रधानों को भी पूर्व सूचना दी जाएगी, ताकि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने लोगों से अपील की है कि उक्त अवधि के दौरान नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न जाएं तथा प्रशासन और परियोजना प्रबंधन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

संक्षिप्त खबरें

सब्जी मंडी एवं भट्टा कुफर स्कूल में आया भूकंप

चमन शर्मा

शिमला। आपदा प्रबंधन को लेकर सोमवार को शिमला शहरी क्षेत्र के सब्जी मंडी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भट्टाकुफर में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके तहत सब्जी मंडी में सुबह 09 बजे रिक्टर स्केल पर 8.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप की सूचना अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम डॉ भुवन शर्मा को प्राप्त हुई। इसके बाद मौके पर तैनात टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ किया।

भूकंप की चपेट में 10 से 14 भवन क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 05 पुरुष और 01 महिला की मौके पर ही मौत दर्ज की गई। इसके अलावा 43 लोग घायल हुए जिसमें 25 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल रहीं। सभी घायलों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया।

रेस्क्यू कार्य 9 बजकर 24 मिनट पर आरंभ हुआ। रेस्क्यू टीम मौके के लिए 09 बजकर 21 मिनट पर रवाना हुई। इसके अलावा 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 53 लोगों को मामूली चोटें आई जिनका उपचार मौके पर स्थापित मेडिकल कैंप में किया गया।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें आपदा से निपटने को लेकर अभ्यास करवाया गया। इसके अलावा मौके पर आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रणनीति को अमलीजामा पहनाया गया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कंट्रोल रूम में मेगा मॉक ड्रिल की पल-पल की अपडेट ली जा रही थी। इसके साथ ही सभी टीमों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा था।

मां चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

राजन पुरी

ऊना। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री चिंतपूर्णी मंदिर में मंगलवार को केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में विधिवत पूजा-अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने देश की सुख-समृद्धि, नागरिकों के कल्याण तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की निरंतर प्रगति के लिए मां के चरणों में प्रार्थना की।

मंदिर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का मंदिर प्रशासन और पुजारियों द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर मां चिंतपूर्णी की विशेष पूजा-अर्चना की और देश में शांति, समृद्धि तथा विकास के लिए कामना की। पूजा-अर्चना मंदिर के पुजारी नव कालिया द्वारा विधिवत मंत्रो%चारण के साथ संपन्न करवाई गई। इस अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष देश के लिए ऐतिहासिक और उपलब्धियों से भरपूर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, आधारभूत ढांचे, डिजिटल क्रांति और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है। उन्होंने माता रानी से प्रार्थना की कि आने वाले समय में भी देश इसी प्रकार विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे और सरकार जनसेवा के अपने संकल्प को और अधिक मजबूती से पूरा कर सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह विशेष रूप से मां चिंतपूर्णी के दरबार में देश की उन्नति, प्रदेश की खुशहाली और करोड़ों देशवासियों के सुखद भविष्य की कामना लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मां चिंतपूर्णी की कृपा से भारत विश्व मंच पर और अधिक मजबूत तथा आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरेगा।

लमलेहड़ा में पुरानी रंजिश के चलते दराट से हमला, तीन लहूलुहान

राजन पुरी

ऊना। पुलिस थाना मैहतपुर के तहत लमलेहड़ा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुए तीन भाईयों पर हमला हुआ है। दराट से हुए हमले तीनों भाई लहूलुहान हुए हैं। पुलिस ने घायल व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में सुरजीत सिंह निवासी लमलेहड़ा ने बताया कि बीते शुक्रवार की रात वह अपनी गाड़ी देखने के लिए घर से बाहर गया था। इसी दौरान गांव के ही बलदेव सिंह, काका और मिटू ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद काका ने पीछे से आकर दराट से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। शोर सुनकर उसके भाई गुरनाम सिंह और कुलवंत सिंह मौके पर पहुंचे। आरोप है कि तीनों आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और रास्ता रोककर हमला किया। घटना में तीनों को चोटें आईं। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण करवाया और एमएलसी रिपोर्ट प्राप्त की। एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी बलदेव सिंह, काका और मिटू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

खड्ड गांव में रास्ते की मिट्टी को लेकर मारपीट, एक गंभीर घायल

राजन पुरी

ऊना। हरोली उपमंडल के खड्ड गांव में रास्ते की सफाई के दौरान हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की मेडिकल रिपोर्ट में एक चोट गंभीर पाए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में राहुल दत्ता निवासी खड्ड ने बताया कि कुछ रोज पहले गांव के कुछ लोग रास्ते की सफाई कर रहे थे और उसके खेत से मिट्टी उठाकर रास्ते में डाल रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया तो कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसे शरीर पर चोटें आईं।

19 जून को होगा जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव, दो-तिहाई बहुमत अनिवार्य

कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव 19 जून को आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार ने सोमवार को प्रधान एवं उपप्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत मीडिया से बातचीत के दौरान दी।

उन्होंने बताया कि 7 जून को जिला परिषद के 14 सदस्यों का गोपनीय शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, जिसके बाद अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि इन दोनों पदों पर चयन के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होगा, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया महत्वपूर्ण और रोचक रहने की संभावना है।

राहुल कुमार ने कहा कि प्रशासन द्वारा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी निर्वाचित सदस्य लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए प्रक्रिया में भाग लेंगे।

जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव स्थानीय विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है, ऐसे में सभी की नजरें अब 19 जून को होने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी हैं।

एआर मेंटर ग्रुप एवं जीजी परामर्श संस्था के निदेशक अरुणेश ठाकुर की यूलिया कासियुना से शिष्टाचार भेंट

कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। कश्मीर ठाकुर एआर मेंटर ग्रुप एवं जीजी परामर्श संस्था के निदेशक अरुणेश ठाकुर ने आज रूस के सरकारी विश्वविद्यालयों के अंतरराष्ट्रीय विभाग की प्रमुख यूलिया कासियुना से एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट की।

इस दौरान भारतीय विद्यार्थियों के लिए रूस में उच्च शिक्षा के अवसरों, मार्गदर्शन तथा सहयोग को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तराखंड से रूस के सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने की जिम्मेदारी पर सहमति बनी। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया, विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, छात्रवृत्ति के अवसरों तथा अध्ययन से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

इस अवसर पर अरुणेश ठाकुर ने कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय विभाग की प्रमुख यूलिया कासियुना का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आर मार्गदर्शन समूह एवं जीजी परामर्श संस्था पर विश्वास जताते हुए यह महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।

अनुराग ठाकुर के सवालों से घबराई कांग्रेस सरकार, जवाब देने के बजाय सफाई पेश करने में जुटी : राकेश ठाकुर

पवन धीमान

हमीरपुर। भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि जब भी भाजपा का कोई नेता प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को उजागर करता है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सरकार की कमियों का आकलन करने के बजाय कांग्रेस नेताओं को मीडिया में सफाई देने के लिए आगे कर देते हैं।

राकेश ठाकुर ने कहा कि ऐसा ही एक मामला पिछले सप्ताह सामने आया, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने जोलसप्पड़ स्थित डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज के भवन लगभग दो वर्ष पूर्व तैयार हो जाने के बावजूद आम जनता को उसकी पूर्ण सेवाएं उपलब्ध न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही अनुराग सिंह ठाकुर ने यह सच्चाई जनता के सामने रखी, मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता इस विषय पर सफाई देने में जुट गए।

राकेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता आज हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को अपनी उपलब्धि बताने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि जनता यह जानना चाहती है कि वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना के लिए आखिर क्या ठोस कदम उठाए थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले 4 मार्च 2014 को मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति अवश्य दी गई, लेकिन उस समय यह केवल एक प्रशासनिक घोषणा बनकर रह गई थी और परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं एवं निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाए।

राकेश ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर गंभीर थी तो मार्च 2014 तक वह क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि चुनावों से ठीक पहले स्वीकृति पत्र जारी करना जनता को प्रभावित करने का एक राजनीतिक प्रयास था।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने उस समय केवल श्रेय लेने की राजनीति की, जबकि परियोजना को वास्तविक गति बाद के वर्षों में मिली।

राकेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद मेडिकल कॉलेज परियोजना के लिए वित्तीय प्रावधानों और कार्यान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत इस मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 180 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई, जबकि मूल परियोजना लागत लगभग 189 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी। बाद के वर्षों में परियोजना का आकार और लागत बढ़ती गई तथा वर्तमान में इसकी लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी है।

रामपुर में फ्लैश फ्लड पर आधारित मॉक एक्सरसाइज आयोजित

लिहान्टू

रामपुर बुशहर। आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की तैयारियों का आकलन करने के उद्देश्य से उपमंडल रामपुर में क्लाउडबर्स्ट एवं फ्लैश फ्लड की काल्पनिक स्थिति पर आधारित एक व्यापक मॉक एक्सरसाइज आयोजित की गई। अभ्यास के दौरान यह परिदृश्य निर्मित किया गया कि सतलुज बेसिन क्षेत्र में 100 मिलीमीटर वर्षा होने से अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे अनेक मकानों को नुकसान पहुंचा है तथा कई लोग प्रभावित क्षेत्रों में फंस गए हैं।

मॉक एक्सरसाइज का आयोजन रिवर बैंक दत्तनगर, नोगली तथा डीएवी स्कूल रामपुर में किया गया। तीनों स्थलों पर विभिन्न बचाव एवं राहत एजेंसियों द्वारा आपदा प्रतिक्रिया एवं रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया।

रिवर बैंक दत्तनगर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और अग्नि शमन, होम गार्ड्स द्वारा संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया गया।

टीमों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाने तथा प्रभावित क्षेत्र से निकासी की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया।

शपथ ग्रहण के साथ ही सेवा का संदेश, जुखाला पंचायत के नव-निर्वाचित प्रधान ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 11 हजार रुपये

कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने आज बिलासपुर स्थित बहुउद्देशीय भाषा एवं संस्कृति भवन के सभागार में जिला के नव-निर्वाचित प्रधानों एवं उप-प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया जब जुखाला पंचायत के नव-निर्वाचित प्रधान हरि राम धीमान ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी ओर से 11,000 रुपये की राशि गूगल पे के माध्यम से भेंट की। पद संभालते ही जनहित को सर्वोपरि रखते हुए किया गया यह योगदान उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। नव-निर्वाचित प्रधान हरि राम धीमान ने कहा कि उन्होंने कुर्सी नहीं, सेवा का मार्ग चुना है और आगे भी समाजहित में कार्य करते रहेंगे।

एमबीबीएस उत्तीर्ण छात्रों की नियुक्ति हेतु 50 प्रतिशत कमीशन व बैच-वाइज भर्ती की मांग

कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। सोमवार को प्रधानों और उप-प्रधानों को शपथ दिलाने पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी को पूर्व जिला कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष एवं जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता सरपाल ठाकुर ने अभिभावकों और छात्रों की ओर से एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में एमबीबीएस पास कर चुके छात्रों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की मांग उठाई गई है। सरपाल ठाकुर ने बताया कि वर्तमान समय में हर वर्ष लगभग 700 से 800 छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर टेस्ट पास कर रहे हैं, जबकि पहले यह संख्या केवल 100 से 200 के बीच होती थी। उस समय सीमित संख्या के कारण अधिकांश छात्रों को आसानी से नियुक्ति मिल जाती थी, लेकिन अब बढ़ती संख्या के चलते बड़ी संख्या में छात्र नियुक्ति से वंचित रह जाते हैं।

ज्ञापन में अभिभावकों और छात्रों ने सरकार से मांग की है कि नियुक्तियों में 50 प्रतिशत कमीशन तथा 50 प्रतिशत बैच-वाइज आधार पर भर्ती की व्यवस्था लागू की जाए, ताकि सभी बैच के छात्रों को समान अवसर मिल सके। उनका कहना है कि इससे न केवल योग्य छात्रों को समय पर रोजगार मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा।

सरपाल ठाकुर ने कहा कि यह मांग पूरे हिमाचल प्रदेश के अभिभावकों और छात्रों की ओर से उठाई गई है और सरकार से इस पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा की गई है।

सरनौहली मेला आस्था, संस्कृति और विश्वास का संगम : राजेश धर्माणी

टीम एक्शन इंडिया

मंडी । ऋषि पराशर की पावन तपोस्थली में आयोजित तीन दिवसीय जिला स्तरीय सरनौहली मेला मंगलवार को श्रद्धा, उत्साह और सांस्कृतिक रंगों के बीच संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता नगर एवं ग्राम योजना, आवास तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने की। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी सोनिया शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। इससे पूर्व मंत्री ने ग्राम पंचायत सेगली में बनने वाले आईटीआई भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि इस भवन के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। औपचारिकताएं पूरी होते ही निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। पराशर पहुंचने पर मंत्री ने देव ऋषि परासर की विधिवत पूजा-अर्चना की तथा मेले में पधारे देवी-देवताओं से प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की संस्कृति और परंपराएं हमारी सबसे बड़ी धरोहर हैं, जिनका संरक्षण और संवर्धन हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वृत्त कटौला की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 15 हजार रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोकनृत्य नाटी में भी भाग लेकर कलाकारों और स्थानीय लोगों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आईटीआई में नए ट्रेड आरंभ करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी, ताकि क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।

बिहूँ प्रीमियम लीग-3 जोगिंद्नगर की टीम रही विजेत, समारोह की जीवन ठाकुर ने की अध्यक्षता विजेता टीम को 22 हज़ार की नक़द राशि

टीम एक्शन इंडिया
संगराय

जोगिंद्रनगर। जोगिंद्रनगर उपमंडल की बिहूँ पंचायत में बिहूँ प्रीमियम लीग-3 का समापन हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर ने की। बिहूँ प्रीमियम लीग के संयोजक सुशील कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 20 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में कोटरोपी जोगिंद्रनगर की टीम विजेता रही, वहीं मच्छयाल की टीम दूसरे स्थान पर रही। मुख्यातिथि जीवन ठाकुर ने विजेता टीम को ट्रॉफी तथा 21 हजार रुपये की नकद राशि भेंटकर सम्मानित किया। उपविजेता मच्छयाल टीम को ट्रॉफी और 11 हजार रुपये की राशि भेंटकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर जीवन ठाकुर ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से जहां खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है, वहीं युवाओं में खेल भावना और आपसी भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने आयोजक समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और भविष्य में भी ऐसे टूर्नामेंट करवाने का आह्वान किया।

बंजार सब्ज़ी मंडी का निर्माण कार्य शीघ्र पुन: शुरू करें प्रदेश सरकार : सुरेंद्र शौरी

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू। बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने जिला कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति के नवनिर्वाचित प्रधानों एवं उपप्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित प्रदेश के माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री चंद्र कुमार जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका स्वागत किया तथा बंजार विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण जनहित के विषय उनके समक्ष प्रमुखता से रखे। विधायक ने क्षेत्र के किसानों एवं बागवानों की वर्षों पुरानी मांग का उल्लेख करते हुए बंजार सब्ज़ी मंडी के मार्केट यार्ड निर्माण कार्य को शीघ्र पुन: प्रारंभ करवाने और निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लगभग सात करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित यह परियोजना वर्ष 2022 से लंबित पड़ी हुई है, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों और बागवानों को अपनी उपज के विपणन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र के कृषि एवं बागवानी क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी तथा किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त विधायक श्री शौरी ने पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2022 में पशु अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत किए

गए बजौरा एवं बाहु पशु औषधालयों को पुन: पशु अस्पताल का दर्जा प्रदान करने की मांग भी मंत्री महोदय के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के माध्यम से बड़ी संख्या में पशुपालकों को सुविधाएं प्राप्त होती है तथा इनके पुन: स्तरोन्नयन से ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। विधायक श्री शौरी ने बंजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित पशु चिकित्सालयों एवं पशु औषधालयों में चिकित्सकों, औषधि वितरकों तथा अन्य आवश्यक कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण पशुपालकों को समय पर उपचार एवं आवश्यक सेवाएं

कोरम के अभाव में नहीं हो सका नगर परिषद सरकाघाट के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव

टीम एक्शन इंडिया

मंडी। नगर परिषद सरकाघाट के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के लिए मंगलवार को निर्धारित चुनाव कोरम के अभाव में सम्पन्न नहीं हो सका। आवश्यक संख्या में पार्षदों की उपस्थिति न होने के कारण चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम एवं प्राधिकृत अधिकारी सरकाघाट राजेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि नगर परिषद में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रिक्त पदों को भरने के लिए आज विशेष बैठक बुलाई गई थी। निर्धारित नियमों के अनुसार बैठक की कार्यवाही संचालित करने के लिए सात

चौंतड़ा में धूमधाम से मनाया गया 17वें कर्मापा का 42वां जन्मदिन

टीम एक्शन इंडिया
संगराय

जोगिंद्रनगर। तिब्बत बौद्ध धर्म के 17वें कर्मापा ग्यालवांग कर्मापा ओग्येन ट्रिनले दोरजे का 42वां जन्मदिन चौंतड़ा में नांगछैन कल्चर कमेटी और तिब्बतियन खाम्पा इंडस्ट्रियल सोसायटी द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूजा-पाठ और केक काटकर खुशी जाहिर की गई तथा बौद्ध गुरु की लंबी आयु की कामना की गई।

तिब्बती बौद्ध धर्म के कर्मा काग्यु वंश के अनुयायियों द्वारा हर वर्ष 17वें कर्मापा का जन्मदिन बहुत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। 17वें कर्मापा ओग्येन ट्रिनले दोरजे का जन्म जून 1985 को ल्हातोक, तिब्बत में हुआ था। 42वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर चौंतड़ा के समस्त तिब्बती समुदाय ने हर्षोल्लास के साथ नाच-गाकर कर्मापा का जन्मदिन मनाया।

इस उपलक्ष्य पर चौंतड़ा पंचायत के नवनियुक्त प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से हिस्सा लिया, जिनमें प्रधान राम सिंह, उप प्रधान भगत राम और वार्ड सदस्य सुरेश कुमार मौजूद रहे। पुलिस चौकी चौंतड़ा से आरक्षी ममता और रजनी भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। इसके अलावा शेरिंग दोरजे, डोलमा, सोनम, जमयांग, प्यार चंद कोहली, कुंचुम लामो, मेरिचाप सहित बड़ी संख्या में तिब्बती समुदाय के लोग उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय राजमार्ग-154 की क्षमता जांचने को एनएचएआई का सर्वे, जोगिंद्रनगर में चौंकाने वाले आंकड़े

टीम एक्शन इंडिया
संगराय

जोगिंद्रनगर । नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154 पर पठानकोट से मंडी तक सड़क पर वाहनों के लोड का आकलन करने के लिए निजी कंपनी डाटा क्रॉप से सर्वे करवाया जा रहा है। डाटा क्रॉप कंपनी के सर्वेयर मोहित मौर्य ने बताया कि पठानकोट से मंडी तक एनएच-154 पर 6 स्थानों - कांगड़ा, परोर खास, घुघर पालमपुर, ढेलू जोगिंद्रनगर, हंगरी प्वाइंट जोगिंद्रनगर तथा नारला में सर्वे किया जाएगा।

मोहित ने बताया कि कांगड़ा और ढेलू जोगिंद्रनगर में एक्सल लोड यानी मालवाहक वाहनों का सर्वे किया जा रहा है, जबकि बाकी चार जगहों पर ओडी सर्वे यानी यात्री वाहनों का सर्वे किया जा रहा है।

किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार : प्रो. चन्द्र कुमार

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू. पुरानी सब्जी मंडी पतलीकूहल में सोमवार को जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार चौधरी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ उसका अवलोकन भी किया। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि खेती प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है और राज्य सरकार किसानों से सीधे जुड़कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि एक बड़ा उद्योग है, जिससे प्रदेश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, जबकि देश की जीडीपी में भी कृषि क्षेत्र का 7 से 8 प्रतिशत योगदान है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कृषि योग्य भूमि सीमित है, इसलिए कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों को खेतों के आकार, मिट्टी की उर्वरता तथा स्थानीय जलवायु के अनुरूप खेती और बागवानी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के मौसम सम्बंधित अध्ययन करने के लिए कृषि अधिकारियों को देहरादून में विशेष प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है । प्रो. चन्द्र कुमार ने कहा कि किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और कृषि संबंधी सभी जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे प्रदेश की सभी मंडियां आपस में जुड़ेंगी और किसानों को अपने उत्पादों के बेहतर मूल्य की जानकारी समय पर मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव और आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है । उन्होंने कहा कि अनुसंधान को किसानों और खेतों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बनाया जा रहा है। कृषि विभाग जायका और आत्मा परियोजना के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों तथा प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत कम करना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना तथा रसायन-मुक्त खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना है।

कुल्लू में आपदाओं से निपटने के लिए '10 वें राज्य-स्तरीय मेगा मॉक अभ्यास' का सफल आयोजन

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला कुल्लू में आज '10वें राज्य-स्तरीय मेगा मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास (दिन और रात) दोनों चरणों में संचालित किया गया, जिसमें भूकंप, बादल फटना और वनाग्नि (जंगलों की आग) जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों को री-क्रिएट कर प्रशासनिक तत्परता को परखा गया। इस मॉक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रतिक्रिया टीमों, सुरक्षा बलों और नागरिक सुरक्षा संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा 'बिजनेस कंटिन्यूटी' (कार्य निरंतरता) को सुनिश्चित करना था। कुल्लू में यह अभ्यास सुबह 9 से 12 बजे तक मॉक अभ्यास की शुरुआत इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम (द्व्रत्र्र) को सक्रिय करने और आपातकालीन परिचालन केंद्रों में तत्काल आवश्यक सुविधाएं बनाने के साथ सम्पन्न हुआ। इसके बाद वायरलेस संचार व्यवस्था पर स्विच किया गया और रिपोर्ट का विश्लेषण करके स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाई गई। स्वयंसेवकों, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड्स द्वारा प्रारंभिक सामुदायिक प्रतिक्रिया दी गई, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। इसी दौरान एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा बलों की मांग की गई।कुल्लू जिला में विभिन्न स्थानों पर आपदा के परिदृश्य रचते हुए अभ्यास किया गया गया। इन परिदृश्य में अखाड़ा के क्षेत्र में भूस्खलन होने से 9 मकान ढह गए, जिनके मलबे में से खोज एवं बचाव अभियान में सभी 8 लोग सुरक्षित निकाले गए। भून्तर के जिया पुल गिर जाने से पुल से गुज़र रही बस में सवार 15 लोगों में से 5 लोग नदी में बह गए। अभियान के दौरान सभी को सुरक्षित बचाया गया जिनमें से एक की मृत्यु हो गई तथा 4 घायलों को तेगूबेहड अस्पताल में उपचार हेतु लाया गया।

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में 18 से 20 वर्ष की युवतियों को योजना से बाहर रखना महिलाओं से अन्याय : पंकज जम्वाल

टीम एकशन इंडिया
संगराय

जोगिंद्रनगर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज जम्वाल ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में किए गए संशोधन पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि 18 से 20 वर्ष की युवतियों को योजना से बाहर करना कांग्रेस के चुनावी धोखे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन साढ़े तीन वर्ष बाद भी यह वादा पूरा नहीं हो पाया। अब सरकार द्वारा योजना के दायरे को सीमित कर 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग की युवतियों को बाहर करना महिलाओं के साथ अन्याय है। पंकज जम्वाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार लगातार नई शर्तें लगाकर लाभार्थियों की संख्या कम कर रही है, जिससे उसकी आर्थिक विफलता उजागर हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से चुनावी वादे के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को बिना भेदभाव 1500 रुपये प्रतिमाह देने की मांग की। साथ ही कहा कि भाजपा इस मुद्दे को जनता के बीच मजबूती से उठाती रहेगी।

नालियों का काम शुरू कर भूली नगर परिषद, आदर्श शहर का सपना दिखाकर बना रहे कबाड़ मार्केट

टीम एक्शन इंडिया
कमल शर्मा

नेरचौक। हिमाचल प्रदेश के तेजी से विकसित हो रहे शहर नेरचौक में नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर स्थानीय व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं। व्यापारियों का आरोप है कि चार माह पूर्व बाजार क्षेत्र में नाली निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन इसे अधूरा छोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप दुकानों के सामने गहरा गड्ढा बन गया है, जिसमें गंदा पानी जमा हो रहा है और आसपास गंदगी फैल रही है।

मुख्य बाजार के व्यापारी कृष्ण ठाकुर, योगेंद्र सिंह, हितेश सैनी, लवली टेलर्स, देवभूमि हैंडलूम तथा वर्मा ढाबा सहित अन्य व्यापारियों ने बताया कि अधूरी नाली के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यह स्थिति कभी भी किसी अप्रिय घटना का कारण बन सकती है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मामले की शिकायत कार्यकारी अध्यक्ष से भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि नगर परिषद सफाई व्यवस्था के नाम पर शुल्क तो वसूल रही है, लेकिन सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल साबित हो रही है।व्यापारियों ने नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष मीना से हस्तक्षेप कर जल्द समस्या का समाधान करवाने की मांग की है। वहीं अध्यक्ष मीना ने कहा कि परिषद का कार्यभार पूरी तरह सुचारू रूप से संभालते ही इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा अधूरी नालियों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा।स्थानीय लोगों का कहना है कि नेरचौक को आदर्श शहर बनाने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मूलभूत सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

नबाही मेले में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

टीम एक्शन इंडिया

मंडी। सरकाघाट के ऐतिहासिक ?श्री नवाही माता मंदिर में वार्षिक मेले के दौरान हर साल रोमांचक वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। स्थानीय आयोजकों जैसे नव दुर्गे क्लब द्वारा मेले के उपलक्ष्य में दो दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमे दस टीमों ने भाग लिया जिसमें बाहरी राज्य रूप में पंजाब, हरियाणा की टीमों ने भी भाग लिया । प्रतियोगिता के समापन अवसर पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव पवन ठाकुर ने बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की । प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबला ऊना और पठानकोट के बीच खेला गया

17 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी

टीम एक्शन इंडिया

मंडी। हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत उप-मंडल-1 सहायक अभियंता ई. नरेश ठाकुर ने बताया कि 11 केवी समखेतर, 11 केवी हॉस्पिटल और 11 केवी पड्डल एचटी लाइनों की आवश्यक मुरम्मत, रख रखाव तथा एचटी लाइन के आस-पास पेड़ों की कांट-छांट का कार्य 17 जून सुबह 10 :00 बजे से शाम 05 :00 बजे तक किया जाना निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कारण इन एचटी लाइनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों लोअर व अप्पर समखेतर, गोल पौड़ी, बालक रूपी, खत्री सभा, मोती बाज़ार, अस्पताल रोड, जोनल अस्पताल, गणपति रोड, पैलेस कॉलोनी, सैण मोहल्ला, सैण मट, आदि।

18 जून को चक्कर मिल्क प्लांट के बाहर धरना देंगे दुग्ध उत्पादक

टीम एक्शन इंडिया
कमल शर्मा

नेरचौक। चक्कर स्थित मिल्क प्लांट में दूध संग्रहण को लेकर नाराज दुग्ध उत्पादकों और व्यापारियों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। करीब 100 दुग्ध उत्पादकों और किसानों ने मंगलवार को बल्ह के एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 18 जून को चक्कर स्थित मिल्क प्लांट के बाहर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों ने स्पष्ट किया कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी।

ज्ञापन सौंपने के दौरान बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी भी मौजूद रहे। इस दौरान किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है।

दूध उत्पादकों का आरोप है कि चक्कर मिल्क प्लांट द्वारा दूध खरीद के लिए न्यूनतम 20 लीटर प्रतिदिन की शर्त लागू कर दी गई है, जिससे छोटे पशुपालक सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि क्षेत्र के अधिकांश पशुपालकों का दूध उत्पादन 20 लीटर से कम है, जिसके चलते उनका दूध नहीं लिया जा रहा और उन्हें कम कीमतों पर निजी स्तर पर दूध बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

किसानों ने सप्ताह में एक दिन घोषित किए गए मिल्क हॉलिडे का भी विरोध किया है। उनका कहना है कि दूध का उत्पादन प्रतिदिन होता है और संग्रहण बंद रहने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

49वें सूत्रधार वर्षगांठ उत्सव की तैयारियों एवं आयोजन की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू। सूत्रधार कला संगम कुल्लू की एक विशेष कार्यकारिणी बैठक संस्था के कार्यालय सूत्रधार भवन में अध्यक्ष दिनेश सेन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में 21 जून से 23 जून 2026 तक ऐतिहासिक लाल चन्द प्रार्थी कला केंद्र तथा अटल सदन, कुल्लू में आयोजित होने वाले भव्य 49वें सूत्रधार वर्षगांठ उत्सव की तैयारियों एवं आयोजन की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई । बैठक में उत्सव को भव्य एवं यादगार बनाने के लिए विभिन्न समितियों की जिम्मेदारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए । बैठक को संबोधित करते हुए संस्था अध्यक्ष दिनेश सेन ने कहा कि 21 जून 2026 का दिन सूत्रधार कला संगम कुल्लू के लिए अत्यंत गौरव एवं हर्ष का अवसर है, क्योंकि संस्था अपने सांस्कृतिक सफर के गौरवशाली 49 वर्ष पूर्ण कर स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रही है । उन्होंने कहा कि वर्ष 1977 से निरंतर कला, संस्कृति एवं समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत सूत्रधार कला संगम ने हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है

जाहलमा नाला में पुल निर्माण कार्य को मिलेगी गति, वैकल्पिक संपर्क मार्गों के निर्माण पर भी जोर : अनुराधा राणा

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू। लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने आज जाहलमा नाला में निर्माणाधीन पुल के प्रगति कार्यों का निरीक्षण किया तथा जोबरंग पुल एवं लिंगर-राशेल वैकल्पिक सड़क मार्ग का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि लिंगर-राशेल वैकल्पिक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि जाहलमा नाला में निर्माणाधीन पुल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना है तथा इसके निर्माण कार्य को और गति देने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक पुलिया के निर्माण के लिए भी बीआरओ तथा लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है। इस दिशा में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिल सके। अनुराधा राणा ने कहा कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है

किसानों की उपज के सुरक्षित एवं समयबद्ध विपणन को लेकर जिला प्रशासन गंभीर : उपायुक्त किरण भड़ाना

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू। लाहौल के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना से मुलाकात कर आगामी मानसून सीजन और वर्तमान कृषि उत्पादन अवधि के मद्देनजर किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चिंताओं को उनके समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जिले में सब्जियों, नकदी फसलों तथा फूलों की फसल कटाई और विपणन का समय निकट है। ऐसे में पिछले वर्षों के आपदा के अनुभवों तथा वर्तमान में जाहलमा नाला की मौजूदा स्थिति को देखते हुए किसानों में अपनी उपज को समय पर मंडियों तक पहुंचाने को लेकर चिंता बनी हुई है। किसानों ने प्रशासन से आग्रह किया कि मानसून अथवा किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कृषि उपज के निर्बाध परिवहन के लिए पूर्व से ही प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों की मेहनत से तैयार फसल को नुकसान न पहुंचे और उसे समय पर बाजार उपलब्ध हो सके। उपायुक्त किरण भड़ाना ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है तथा किसानों की उपज को सुरक्षित एवं समयबद्ध रूप से बाजारों तक पहुंचाने के लिए बहु-आयामी रणनीति पर कार्य किया जा रहा है।

हमारी संस्कृति ही हमारी वास्तविक धरोहर-संजय अवस्थी

टीम एक्शन इंडिया
मनीष

सोलन। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि हमारी संस्कृति ही हमारी वास्तविक धरोहर हैं। संजय अवस्थी आज अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बखालग में बनिया देवी मेले में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे। विधायक ने इससे पूर्व माँ वन दुर्गा मंदिर बनिया देवी में पूजा-अर्चना की और क्षेत्रवासियों के खुशहाली का कामना की। संजय अवस्थी ने कहा कि समृद्ध देव संस्कृति का संरक्षण करना हम सभी का उत्तरदायित्व है और जन-जन के सामूहिक प्रयासों से ही संस्कृति का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित होता है। उन्होंने कहा कि मेले हमारी संस्कृति के परिचायक हैं और मेलों एवं उत्सवों का संरक्षण युवा पीढ़ी को परम्पराओं की जानकारी प्रदान करते है। मेलों से युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से रू-ब-रू होती है। उन्होंने कहा कि मेले व उत्सव न केवल संस्कृति व परम्पराओं को जीवित रखने के लिए आवश्यक है बल्कि आपसी भाईचारे को बढ़ाने का माध्यम भी है। इंटरनेट के इस युग में लोगों के मध्य भाईचारे बढ़ाने के लिए मेले व त्यौहारों की महत्वता और अधिक बढ़ गई है। विधायक ने कहा कि बनिया देवी मंदिर का इतिहास लगभग 450 वर्ष पुराना है। इस प्राचीन मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर-दूर से आते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। इससे जहां क्षेत्र का विकास होगा वहीं रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण के प्रारंभिक कार्य के लिए 05 लाख रुपए, झासी माता देवी में ग्रिल लगाने के लिए 01 लाख रुपए, गोपाल के घर से मंझली बेड धरनो मार्ग के निर्माण के लिए 02 लाख रुपए देने की घोषणा की।

मोदी ने 12 वर्षों में बदली देश की तस्वीर : सुरेश कश्यप

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र आज देश के विकास का आधार बन चुका है और मोदी सरकार ने देश की तस्वीर ही नहीं बल्कि तकदीर भी बदलने का काम किया है। नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचा है। गरीब कल्याण, किसानों के उत्थान, महिलाओं के सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे के विस्तार में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि विकास की इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश को श्री रेणुकाजी बहुउद्देश्यीय परियोजना, आईआईएम सिरमौर, नए मेडिकल कॉलेजों, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, रेलवे परियोजनाओं और पर्यटन विकास जैसी अनेक महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं, जिनसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को मजबूती मिली है।

शूलिनी यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप में 300 से ज़्यादा छात्र शामिल हुए

टीम एक्शन इंडिया
मनीष

सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में सैमसंग सॉल्व फॉर टुमॉरो के तहत आयोजित एक डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप में हिमाचल प्रदेश भर से 300 से ज़्यादा छात्र इकट्ठा हुए। उन्होंने यह सीखा कि सिर्फ़ टेक्नोलॉजी बनाने के बजाय, समुदाय की असल ज़रूरतों को समझकर कैसे इनोवेशन किया जा सकता है। यह वर्कशॉप सैमसंग इंडिया के खास इनोवेशन प्रोग्राम सैमसंग सॉल्व फॉर टुमॉरो 2026 का हिस्सा है। यह प्रोग्राम 14 से 22 साल के युवाओं को ए आई, हेल्थ और एजुकेशन, पर्यावरण की स्थिरता, और खेल व टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों की चुनौतियों के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित समाधान विकसित करने में सक्षम बनाता है। यह फ्रेमवर्क प्रतिभागियों को उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों और भावनाओं को समझने, समस्याओं की असल वजहों का पता लगाने, नए आइडिया सोचने, प्रोटोटाइप बनाने और समाधानों को टेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह वर्कशॉप पूरे भारत में छात्रों तक सीधे डिज़ाइन थिंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा पहुँचाकर, ज़मीनी स्तर पर इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने की सैमसंग की व्यापक कोशिश का हिस्सा है। 2026 एडिशन के तहत, सैमसंग देश भर के 100 शहरों में वर्कशॉप आयोजित कर रहा है, जिससे युवा इनोवेटर्स को स्थानीय चुनौतियों की पहचान करने और राष्ट्रीय महत्व वाले समाधान विकसित करने के अवसर मिल रहे हैं। इस प्रोग्राम का समापन टॉप चार विजेता टीमों को एफआईटीटी,आईआईटी दिल्ली में 2 करोड़ रुपये के इनक्यूबेशन ग्रांट मिलने के साथ होगा; साथ ही, उन्हें अपने आइडिया को मेंटरशिप कीकत में बदलने में मदद के लिए मेंटरशिप, ट्रेनिंग और प्रोटोटाइपिंग सपोर्ट भी मिलेगा। सॉल्व फॉर टुमॉरो 2026 के लिए आवेदन 3 जुलाई, 2026 तक खुले रहेंगे।

औहर पंचायत में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एसपी को सौंपा ज्ञापन

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर, जिला की औहर पंचायत में लगातार बढ़ रही चोरी और सेंधमारी की घटनाओं से परेशान लोगों को राहत दिलवाने के लिए ग्राम पंचायत के प्रतिधिनियों ने पंचायत प्रधान देश राज शर्मा की अगुवाई में एसपी बिलासपुर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों पर अंकुश लगाकर लोगों को राहत दिलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायत के विभिन्न गांवों में बीते दो महीनों के दौरान 11 स्थानों पर चोरों द्वारा चोरी अथवा चोरी के प्रयास किए जाने के मामलों से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। रात के समय अज्ञात लोग घरों के आसपास घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिससे परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। औहर पंचायत प्रधान देशराज शर्मा ने बताया कि पिछले दो महीनों के भीतर पंचायत क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि 18 मई की रात दड़याणा गांव में बली राम, राहियां.पलाथीं में तुलसी राम तथा दड़याणा में ही सुरेश कुमार के घर पर चोरी का प्रयास किया गया। इसके बाद 22 मई की रात भजवाणी.रोपा में नंद लाल, भजवाणी में सुभाष शर्मा तथा कल्लर में बलबीर सिंह के घरों में सेंधमारी करने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि 25 मई की रात औहर में सोहन लाल धीमान के घर को निशाना बनाया गया। वहीं, 9 जून को भजवाणी में मदन चंदेलए सतीश कुमार और रमेश कुमार के घरों में भी चोरों ने घुसने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त 10 जून को बड़ोआ गांव में बसंदी राम के घर पर भी ऐसी ही घटना सामने आई। प्रधान देशराज शर्मा ने कहा कि लगातार सामने आ रही घटनाओं के कारण लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।

बिलासपुर में शुरु हुआ जनगणना 2027 का प्रथम चरण

बिलासपुर, कश्मीर ठाकुर

उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत जिला बिलासपुर में आज से मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य आरंभ कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण चरण 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा, जिसके दौरान प्रगणक घर.घर जाकर निर्धारित जानकारी एकत्र करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वगणना की अवधि 15 जून को समाप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है। प्रगणक जानकारी एकत्र करने के लिए एचएलओ मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे। जिन नागरिकों ने 1 जून से 15 जून 2026 के दौरान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वगणना पूरी की हैए उन्हें अपनी स्वगणना आईडी प्रगणकों को उपलब्ध करवानी होगी। राहुल कुमार ने बताया कि प्रदेशभर में 80,486 लोगों ने स्वगणना कीए जिनमें से 71,414 लोगों ने प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कियाए जबकि 9,072 लोगों ने स्वगणना शुरू की

भाजपा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह को लेकर जिला प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी: सोनल शर्मा

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर, बिलासपुर में आयोजित पंचायत प्रधान एवं उपप्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। यह कार्यक्रम एक सरकारी एवं संवैधानिक आयोजन था, जिसका उद्देश्य नव.निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाना था। ऐसे कार्यक्रम में प्रशासन की निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता सर्वोपरि होनी चाहिए। प्रैस को जारी बयान में जिला मीडिया प्रभारी सोनल शर्मा ने कहा कि यदि यह कार्यक्रम पूर्णत: सरकारी थाए तो फिर कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्षा, प्रदेश एवं जिला स्तर के कांग्रेस पदाधिकारियों की उपस्थिति किस आधार पर सुनिश्चित की गई और यदि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया। जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सरकारी कार्यक्रमों में केवल सत्ताधारी दल के पदाधिकारियों को ही स्थान दिया जाएगा और विपक्षी दलों की अनदेखी की जाएगी। यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है, बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। जिलाधीश का पद किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि पूरे जिले और सभी नागरिकों का होता है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप शर्मा भाजपा में शामिल

एसपी जैरथ

नाहन। जिला सिरमौर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने भाजपा की रीति-नीति और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी परिवार का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। संदीप शर्मा कांग्रेस संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। वह जिला महासचिव, जिला मीडिया प्रभारी तथा नाहन विधानसभा क्षेत्र युवा कांग्रेस अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।

उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने नाहन चौगान में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उपप्रधानों को शपथ दिलाई

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन। उद्योग, संसदीय कार्य एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज जिला सिरमौर के नाहन चौगान में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधान व उप-प्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता करते हुए जिला के समस्त 273 प्रधान तथा 273 उप-प्रधानों को विधिवत रूप से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाकर पंचायती राज संस्थाओं में उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर उन्होंने नव निर्वाचित प्रधानों तथा उप-प्रधानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाएं प्राथमिक प्रजातंत्र की मूल इकाइयां है। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इन संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जनता अपने प्रतिनिधि को बहुत विश्वास और अकांक्षाओं से चुनती है इसलिए सभी चुने हुए प्रतिनिधि बिना पक्षपात के पूर्ण इमानदारी, कर्मठता व पारदर्शिता से कार्य करने का संकल्प लें।

उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण विकास की अधिकतर योजनाएं पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और इन योजनाओं के तहत करोड़ों रूपये की धनराशि पंचायतों को प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं का उचित प्रबन्धन तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करना पंचायत प्रतिनिधियों की अहम जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि 16वें वित्तायोग के तहत सिरमौर जिला में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित वर्ष 2026-27 सहित आगामी पांच वर्ष में कुल 226.22 करोड़ रूपये की

बिलासपुर नगर परिषद की कमान जमना देवी के हाथ, नरेंद्र पंडित उपाध्यक्ष

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर, नगर परिषद बिलासपुर के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के पुराने गृह विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर सदर के तहत आने वाली इस नगर परिषद पर लगातार दूसरी बार भगवा परचम लहराया है। मंगलवार को एसडीएम डॉ. राजदीप सिंह की अध्यक्षता में नगर परिषद कार्यालय में संपन्न चुनाव में सर्वसम्मति से भाजपा समर्थित जमना देवी को अध्यक्ष तथा नरेंद्र पंडित को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। ताजपोशी के बाद सदर के विधायक त्रिलोक जमवाल की अगुवाई में नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्षए अन्य पार्षदों तथा भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने ढोल.नगाड़ों के साथ रैली निकाली। साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और बाबा नाहर सिंह मंदिर में पूजा.अर्चना करके आशीर्वाद भी लिया। बिलासपुर नगर परिषद में भाजपा ने लगातार दूसरी बार जीत का परचम लहराया है। 11 सदस्यीय नगर परिषद में पिछली बार भाजपा समर्थित 7 पार्षद चुने गए थे। इस बार विधायक त्रिलोक जमवाल के नेतृत्व में भाजपा ने पिछली बार की तुलना में और अधिक शानदार प्रदर्शन किया है। लिहाजा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा तय था।

पुरूष तीन और महिला चार महीने के बाद कर सकती हैं रक्तदान: मस्त राम

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सदर ब्लॉक मारकंड के सौजन्य से विश्व रक्तदान दिवस नम्होल में मनाया गया। बीएमओ डॉ सुरेंद्र सिंह बावा ने बताया कि विश्व रक्तदान दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस के संयुक्त पहल द्वारा 2004 में पहली बार आयोजित किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए क्योंकि एक रक्तदाता तीन व्यक्तियों की जान बचाता है। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में रक्त का अभाव रहता है। ऐसे में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय दिवस हमें याद दिलाता है कि जरूरतमंद लोगों तक रक्त पहुंचे और किसी की भी मौत रक्त के अभाव की वजह से ना हो। स्वास्थ्य शिक्षक मस्त राम ने कहा कि बीमारियों आपदाओं और दुर्घटनाओं से पीड़ित सभी उम्र के लोगों का जीवन बचाने के लिए सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग रक्तदान करते समय डरते हैं, लेकिन इसे कोई खतरा नहीं होता। उन्होंने कहा की पुरुष तीन महीने में एक बार और महिला चार महीने मे एक बार रक्तदान कर सकते है।

राजगढ़ में कार से 4.80 ग्राम चिट्टा बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन। पुलिस को गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि शुभम ठाकुर निवासी गांव चुन्नी, डाकघर एवं तहसील राजगढ़ अपने दो साथियों विवेक चौहान और मिथुन आर्य के साथ एक कार में चिट्टा लेकर गिरिपुल-सोलन क्षेत्र से राजगढ़ की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू कर दी। डिटेक्शन सेल राजगढ़ की टीम ने कोटली क्षेत्र में नाकाबंदी कर वाहन नंबर HP 63-3060 को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से कुल 4.80 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद किया। बरामदगी के बाद आरोपियों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना राजगढ़ में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

18 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित

सोलन। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवश्यक रखरखाव के दृष्टिगत 18 जून, 2026 को 33/11 के.वी. उप केन्द्र ओच्छघाट से संचालित कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता सोलन राहुल वर्मा ने दी। राहुल वर्मा ने कहा कि 18 जून, 2026 को प्रात: 08.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक जटोली, मझगांव, कोठों, कुन्दला, जीरों प्वाइट, ओच्छघाट, नौणी का प्रांगण, नौणी का बाज़ार, धारों की धार, कोईघाट, बदलेच, पंडाह, थुरान एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

उन्होंने कहा कि इसी दिन शूलिनी विश्वविद्यालय, टटूल, मंझोली, क्यार, नगाली, नंदल, कालाघाट, दोलांजी, एल.आर. इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एवं आस-पास के क्षेत्रों में लोडिंग स्थिति की वास्तविकता के अनुसार विद्युत आपूर्ति बाधित हो सकती है।

संक्षिप्त खबरें

रैम्प और उद्योग 4.0 तकनीकों पर परवाणू में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

टीम एक्शन इंडिया
मनीष

सोलन। उद्योग विभाग केन्द्र परवाणू में आज 'एम.एस.एम.ई. प्रदर्शन को बढ़ावा और गति देना रैम्प' पहल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उद्योग 4.0 तकनीकों को अपनाने के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना था। कार्यक्रम में सी.ई.एल. के विशेषज्ञ इलियाराजा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.ई.) इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, स्मार्ट विनिर्माण, क्लाउड कंप्यूटिंग, उद्यम संसाधन योजना और ग्राहक संबंध प्रबंधन (सी.आर.एम.) जैसी डिजिटल तकनीक एम.एस.एम.ई. को अपने कार्यों का आधुनिकीकरण करने, गुणवत्ता सुधारने, समग्र उपकरण प्रभावशीलता बढ़ाने और वास्तविक समय के उपयोग मामलों के साथ लागत कम करने में मदद कर सकती हैं। कार्यक्रम में अवगत करवाया गया कि ओपन मार्केट एक्सेस पाने के लिए एम.एस.एम.ई. टीम इनिशीटिव के पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है। एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा समर्थित रैम्प पहल का मुख्य उद्देश्य एम.एस.एम.ई. पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देना और उद्योगों की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता का निर्माण करना है। जागरूकता सत्र में हिमाचल प्रदेश के उद्यमों में डिजिटल परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए रैम्प के तहत उपलब्ध योजनाओं, टूलकिट और सहायता तंत्रों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने स्मार्ट एमएसएमई के साथ-साथ सभी सरकारी योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछे तथा क्लस्टर स्तर पर उद्योग 4.0 समाधानों को लागू करने के व्यावहारिक विषयों पर चर्चा की

सरकारी ई-बाज़ार और ऑनलाइन व्यापार पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित

टीम एक्शन इंडिया
मनीष

सोलन। उद्योग विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रदर्शन संवर्धन एवं तीव्रता कार्यक्रम (रैम्प)' के अंतर्गत आज कुनिहार में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला उद्योग केन्द्र के प्रबंधक विनय वर्मा ने की। विनय वर्मा ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों तथा पंचायत प्रतिनिधियों को डिजिटल साधनों, ऑनलाइन व्यापार मंचों, सरकारी ई-बाजार तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम समूह विकास योजना से जोड़कर सशक्त बनाना था। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि रैम्प कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित ऐसे प्रशिक्षण ग्रामीण उद्यमियों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी ई-बाज़ार तथा ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से सोलन जिला के स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं।

इस अवसर पर प्रतिभागियों को उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं तथा ऑनलाइन व्यापार मंचों के माध्यम से बाज़ार विस्तार की जानकारी प्रदान की। सामाजिक माध्यमों के जरिए प्रचार-प्रसार, व्हाट्सऐप व्यापार सेवा, डिजिटल भुगतान तथा ऑनलाइन पहचान निर्माण के व्यावहारिक उपायों पर विशेष बल दिया।

देश के टॉप 25 अधिकारियों में सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा

टीम एक्शन इंडिया
मनीष

सोलन। देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका 'फेम इंडिया' के देश व्यापी सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िला के उपायुक्त मनमोहन शर्मा का टॉप 25 ज़िला अधिकारियों में स्थान पाना जहां पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है वहीं सोलन ज़िला के लिए स्वर्णिम उपलब्धि है। शांत और सरल स्वभाव के धनी मनमोहन शर्मा जहां हर समय आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं वहीं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ज़िला के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम को वह नेतृत्व प्रदान करते हैं जो योजनाओं के माध्यम से विकास के लाभ कतार में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक समय पर पंहुचाने का ज़रिया बनता है। वर्ष 2013 बैच के हिमाचल प्रदेश काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनमोहन शर्मा हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक सेवा के उन प्रतिष्ठित अधिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी शांत कार्यशैली, जनसरोकार और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण से प्रशासनिक जगत में विशेष पहचान बनाई है। फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ ज़िलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी मनमोहन शर्मा को 'कर्तव्यनिष्ठ' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है। अपने प्रशासनिक जीवन में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं। नालागढ़ में उपमण्डलाधिकारी, सिरमौर ज़िला में अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में ज़िला स्तर पर ठोस निर्णयों को धार दी तो वहीं प्रदेश स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, शहरी विकास निदेशक, शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटिड में कार्मिक एवं वित्त निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर प्रदेश हित को साधने में योगदान दिया।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice Invitation for Bids (IFB)
The Executive Engineer, DaulatpurChowk Division, HP. PWD, DaulatpurChowk -177204 on behalf of Governor of Himachal Pradesh invites the online bids on **percentage rate** in electronic tendering system in 2 covers for the under mentioned work from the eligible and approved class of contractors/Firm registered with HPPWD.

Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest money	Time Limit	Cost of Form	Class of Contractor
1	Repair & Restoration of Rain Damages on link road GagretDaulatpur road to Adarsh Colony MohallaLoharaKumharanTrali and MohallaGuggaPanga in village MawaKohlan Km 0/0 to 2/600, (SH: Providing and laying Bituminous Concrete laid with paver finisher in Various RD's) **Under PDNA 2023**	1461118.00	29000.00	Three Month	500-	Class-A to D
2	Repair & Renovation of PHC Shivpur (Mubarikpur) tehsil AmbDistt. Una (H.P) (SH:- Repair and water proofing of existing roof) Under Deposit	375086.00	7500.00	Three Month	350-	Class-D
3	Repair & Restoration of Rain Damages on link road to ShaheedGurdev Singh to Village Deoli Km 0/0 to 3/070, (SH: Providing and laying Bituminous Concrete laid with paver finisher in Various RD's) **Under PDNA 2023**	1019620.00	20400.00	Three Month	500-	Class-D
4	Repair & Restoration of Rain Damages on Daulatpur Shankernager Road from Km 0/0 to km-13/740, (SH:- Repair of Damages & Extension of Slab culvert at RD 4/930 & RCC slab culvert 6.00 Mtr. Span at RD 2/560 and U-Shape Drain at Drain at RD 4/665 to 4/780 LHS, Drain at RD 5/840 to 5/940 LHS, Drain at RD 6/480 to 6/560, Drain RD 8/480 to 8/600 RHS, Drain RD 10/800 to 10/905 LHS and Retaining/Edge wall at RD 1/625 to 1/655 LHS, RD 1/845 to 1/868 LHS, RD 2/930 to 3/030, RD 3/460 to 3/560, RD 8/620 to 8/650 RHS, RD 8/680 to 8/710 RHS and 8/800 to 8/900 and C.C Shoulder at Various RD's) **Under PDNA 2023**	8953931.00	186000.00	Six Month	2000-	Class-C
5	Repair & Restoration of Rain Damages on link road GagretDaulatpur road to Adarsh Colony MohallaLoharaKumharanTrali and MohallaGuggaPanga in village MawaKohlan Km 0/0 to 2/600, (SH:- P/L 300mm dia RCC Hume pipe with chamber for drainage of Household water road side and U-Shape Drain & Retaining wall/Edge wall at Various RD,s) **Under PDNA 2023**	948985.00	19000.00	Three Month	350-	Class-D

1. Availability of Bid Document and mode of submission. The bid document is available online and bid should be submitted in online on website http://hptenders.govt.in.
2. The bidders are advised to note the other details of the tenders from the website http://hptenders.gov.in.
3. **Key Dates:**

1	**Date/Time of online Publication**	**22.06.2026 (05.00 PM)**
2	Documents download Start and end date/time	**22.06.2026 (05.00 PM) to 30.06.2026 (05.00 PM)**
3	Bid submission Start and end date/time	**22.06.2026 (05.00 PM) to 30.06.2026 (05.00 PM)**
4	**Date of technical bid opening**	**01.07.2026 at 11.00 AM**

Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidder's responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.
The undersigned has right to extend or cancel the bids without declaring any reasons thereof.
Executive Engineer,
DaulatpurChowk Division,
HPPWD DaulatpurChowk.
RO No. 1204/2026-2027

संपादकीय

सार्वजनिक जीवन में विश्वास की पूंजी

विश्वास और भरोसा ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। सार्वजनिक जीवन में जन विश्वास गंवाने वाला व्यक्ति किसी योग्य नहीं रह जाता। हाल ही में भारतीय राजनीति में जन विश्वास से जुड़ी दो अहम घटनाएं हुई। पहली घटना में एक नेता ने जनविश्वास की पूंजी खो दिया। वहीं, दूसरी घटना में नेता ने जनविश्वास की पूंजी को सहेजा ही नहीं बल्कि हर बीतते दिन के साथ उसमें वृद्धि भी की। पहली घटना 4 मई की है। इस दिन जन विश्वास खो चुकी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तृणमूल और ममता से नाराजगी का आलम यह था कि स्वयं ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई। आज ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की जो दुर्दशा हो रही है, उसकी जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं बल्कि वह स्वयं हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद अपना अलग गुट बना चुके हैं। स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है, जब किसी राजनीतिक दल का इतनी तेजी से विघटन हुआ हो। या किसी नेता की तथाकथित साख चुनाव हारने के चंद दिनों में ही औंधे मुंह गिरी हो। सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी को मंदिर जाने की याद आई। कालीबाड़ी दर्शन करने पहुंची ममता बनर्जी को लोगों ने पूरी तरह अनदेखा किया। डेढ़ दशक तक सूबे का मुख्यमंत्री रहने वाले नेता की जनता इस हद तक उपेक्षा करे तो यह सिर्फ चुनावी हार नहीं, जनविश्वास के टूटने का संकेत होता है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से आजिज जनता आज उसके नेताओं का अंडे, टमाटर, जूते और मार कुटाई से सत्कार कर रही है। तृणमूल के नेताओं को देखकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो पिछले 15 वर्षों से तृणमूल नेताओं की तानाशाही, गुण्डागर्दी और अत्याचार चुपचाप सह रहे थे। तृणमूल नेताओं के प्रति जनता का व्यवहार उनके स्वाभाविक क्रोध, कुंठा, निराशा और हताशा का परिणाम है। ममता सरकार के डेढ़ दशक के शासन के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकताओं की हत्या व अपहरण, पोलिंग एजेंटों की पिटाई, बमबाजी, गोलीबारी, बूथों पर तोड़फोड़, वोटों की लूट, प्रत्याशियों व उनके परिवार के सदस्यों को धमकियां, ये सब बंगाल में आम बातें हो चुकीं थीं। भाजपा के दावों को मानें तो साल 2021 में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुई हिंसा में टीएमसी समर्थकों ने 300 से अधिक भाजपा कार्यकताओं की हत्या की थी।

तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि राज्य में लोकतंत्र सांस नहीं ले पा रहा है। मुख्यमंत्री और प्रशासन मूकदर्शक बने हुए हैं। दूसरी घटना 10 जून को हुई। इस दिन नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे किए, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पूरे किए गए 4,398 दिनों के कार्यकाल से ज्यादा है।

नई दिल्ली कार्यालय
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

चंडीगढ़ कार्यालय
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

सोनीपत कार्यालय
ऑफिस no. 11, ग्राउंड फ्लोर पवन मेगा मॉल सुभाष चौक सोनीपत

शिमला कार्यालय
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

ऊना कार्यालय
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

रोजगार का सूखा, विकास की हरियाली: युवा भारत की असली तस्वीर क्या?

आरके जैन अरिजीत

> मुद्रास्फीती पर नियंत्रण, बुनियादी ढाँचे का विस्तार और डिजिटल अर्थव्यवस्था का सशक्तीकरण निस्संदेह महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं, किंतु केवल इनके बल पर रोजगार संकट का स्थायी समाधान संभव नहीं है। ग्रामीण भारत को नई शक्ति और गति देने के लिए फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, हस्तशिल्प, लघु उद्योगों तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापक और लक्षित निवेश की आवश्यकता है। यदि रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे, तो पलायन कम होगा और क्षेत्रीय असमानताएँ भी घटेंगी

देश के राजमार्ग विस्तृत हो रहे हैं, हवाई अड्डे आधुनिक बन रहे हैं, डिजिटल अर्थव्यवस्था नए कीर्तिमान गढ़ रही है और भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। लेकिन इस चमकदार विकास के बीच एक प्रश्न लगातार उठ रहा है–यदि प्रगति इतनी तेज है, तो रोजगार के अवसर क्यों सिकुड़ रहे हैं? हालिया आँकड़ों के अनुसार, मई 2026 में बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत तक पहुँचना केवल एक आर्थिक संकेतक नहीं, बल्कि लाखों युवाओं, ग्रामीण परिवारों और शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती चिंता का प्रतिबिंब है। विकास की रफ्तार बढ़ रही है, पर रोजगार उसका साथ नहीं दे पा रहा। यही असंतुलन आज भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती बन गया है। क्या रोजगार सृजन के बिना विकास की यह यात्रा सचमुच पूर्ण कही जा सकती है? इस चुनौती का सबसे गहरा असर ग्रामीण भारत में दिखाई देता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) के अनुसार मई 2026 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। यह आँकड़ा भले छोटा लगे, पर इसके पीछे की सच्चाई कहीं अधिक गंभीर है। गाँव का युवा अब केवल खेती के सहारे अपना भविष्य नहीं देखता। कृषि आय की अनिश्चितता, बढ़ती लागत और सीमित अवसरों ने उसका भरोसा डगमगा दिया है।

वहीं गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजन की गति भी अपेक्षित नहीं रही। नतीजतन, लाखों युवा या तो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं या बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। मनरेगा में बढ़ती मांग इस बात का स्पष्ट संकेत है कि रोजगार संकट अब गाँवों की चौखट तक पहुँच चुका है। शहरी क्षेत्रों की तस्वीर भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। यद्यपि शहरी बेरोजगारी दर 6.4 प्रतिशत रही, लेकिन रोजगार बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने अवसरों को सीमित कर दिया है। जिन शहरों को कभी संभावनाओं का केंद्र माना जाता था,

वहीं आज हजारों योग्य युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। आईटी और सेवा क्षेत्र, जो लंबे समय तक रोजगार वृद्धि के प्रमुख आधार रहे, अब अपेक्षाकृत धीमी गति से अवसर पैदा कर रहे हैं। तकनीकी बदलावों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने भी रोजगार के नए अवसरों को प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप, शहर अब केवल उम्मीदों ही नहीं, बल्कि बढ़ती निराशा के भी केंद्र बनते जा रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति युवाओं की है। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर लगभग 15 प्रतिशत (मार्च 2026 में 15.2%) तक पहुँचना केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि भविष्य को लेकर बढ़ती असुरक्षा का संकेत है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी लाखों युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। युवा महिलाओं की स्थिति और भी गंभीर है, जिनके लिए अवसर अपेक्षाकृत कम हैं। शिक्षा संस्थानों से निकलने वाले युवाओं के हाथ में डिग्रियाँ तो हैं, लेकिन उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल का अभाव अक्सर उनके मार्ग में बाधा बन जाता है। यही बढ़ता स्किल गैप भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को शक्ति के बजाय चुनौती में बदलने का खतरा पैदा कर रहा है। इस स्थिति ने स्वाभाविक रूप से सरकार पर भी दबाव बढ़ाया है। पीएम किसान, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं ने रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक पहल की है, लेकिन व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन अब भी अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका है। विनिर्माण क्षेत्र में ह्यचाइना प्लस वनह्न रणनीति ने भारत के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं, किंतु उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार में बदलने की प्रक्रिया अभी अधूरी है। विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र वित्तीय चुनौतियों, सीमित ऋण उपलब्धता और अन्य संरचनात्मक बाधाओं से जूझ रहा है, जबकि सबसे अधिक रोजगार सृजन की क्षमता इसी क्षेत्र में निहित है। वास्तविक आवश्यकता अब ऐसी आर्थिक दृष्टि की है, जिसमें विकास और रोजगार को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक-दूसरे का आधार माना जाए।

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, बुनियादी ढाँचे का विस्तार और डिजिटल अर्थव्यवस्था का सशक्तीकरण निस्संदेह महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं, किंतु केवल इनके बल पर रोजगार संकट का स्थायी समाधान संभव नहीं है। ग्रामीण भारत को नई शक्ति और गति देने के लिए फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, हस्तशिल्प, लघु उद्योगों तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापक और लक्षित निवेश की आवश्यकता है। यदि रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे, तो पलायन कम होगा और क्षेत्रीय असमानताएँ भी घटेंगी। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है। सुरक्षित कार्य वातावरण, कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर लाखों महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सकता है। साथ ही शिक्षा संस्थानों और उद्योग जगत के बीच मजबूत एवं व्यावहारिक तालमेल स्थापित करना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ताकि युवाओं को केवल डिग्री नहीं, बल्कि वास्तविक रोजगार योग्य कौशल भी प्राप्त हो सके। रोजगार का प्रश्न केवल नौकरी तक सीमित नहीं है; यह आत्मसम्मान, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय प्रगति से जुड़ा एक गहन एवं व्यापक विषय है। यह आँकड़े वर्तमान साप्ताहिक स्थिति पर आधारित हैं, जो अल्पकालिक बेरोजगारी को अधिक स्पष्ट दिखाते हैं, जबकि सामान्य स्थिति (वार्षिक) में यह दर लगभग 3.2 प्रतिशत रहती है। दरअसल, यह संकट एक बड़ा अवसर भी है।

भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा युवा कार्यबल बनने की क्षमता है, पर यह तभी संपदा बनेगा जब रोजगार को राजनीतिक विमर्श से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय संकल्प बनाया जाए। 5.5 प्रतिशत बेरोजगारी दर चेतावनी देती है कि विकास का अर्थ केवल ऊँची जीडीपी, निवेश या चमकते शहर नहीं हैं। विकास तभी सार्थक है जब वह युवाओं को काम, परिवारों को सुरक्षा और समाज को विश्वास दे। ग्रामीण भारत की उम्मीदों को केंद्र में रखकर रोजगार-प्रधान और समावेशी नीतियाँ अपनाई जाएँ, तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है, वरना विकास की चमक के पीछे बेरोजगारी की परछाई और गहरी होती जाएगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक दौर

कुमार सिद्धार्थ

दुनिया के ऑटोमोबाइल बाजार में बड़ा बदलाव धीमे-धीमे आकार ले रहा है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली पारंपरिक गाड़ियाँ, जो पिछले सौ वर्षों से आधुनिक परिवहन व्यवस्था की पहचान रही हैं, अब धीरे-धीरे अपनी पकड़ खो रही हैं। उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन ले रहे हैं। हाल में प्रकाशित एक अध्ययन ने यह दावा किया है कि यूरोप और चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अब निर्णायक मोड़ पर पहुँच चुकी है, बाजार स्वयं इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में आगे बढ़ रहा है और पारंपरिक ईंधन आधारित वाहनों की वापसी मुश्किल होती जा रही है। यह केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और वैश्विक राजनीति तक असर डालने वाला बदलाव है। सवाल यह है कि इस वैश्विक परिवर्तन के बीच भारत कहाँ खड़ा है? यूरोप और चीन के संदर्भ में किए गए अध्ययन का सार है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से कई गुना बढ़ रही है, यानी हर कुछ वर्षों में इनकी संख्या लगभग दोगुनी हो रही है और इन देशों में यह बाजार अब अपने बल पर आगे बढ़ने लगा है। शोधकताओं के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री, पेट्रोल-डीजल कारों की घटती मांग, बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते विकल्प और कीमतों में कम होता अंतर इस बात के संकेत हैं कि अब बाजार तेजी से बदलाव की दिशा में बढ़ चुका है, जहाँ से पुराने ढर्रे पर लौटना आसान नहीं होगा। चीन और यूरोप में यह परिवर्तन केवल बाजार की ताकत से नहीं आया, बल्कि वर्षों की नीति, सब्सिडी, सरकारी निवेश और उद्योग की तैयारी ने मिलकर इसे संभव बनाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और तेजी से शहरीकरण, बढ़ती आय, ऊर्जा आयात और प्रदूषण जैसी चुनौतियों के बीच परिवहन का भविष्य तय करने की स्थिति में है। भारत की सड़कों पर आज भी पेट्रोल और डीजल वाहन हावी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की उपस्थिति अब केवल प्रयोगात्मक नहीं रही। दोपहिया और तिपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक बसें भी धीरे-धीरे जगह बना रही हैं। लेकिन चारपहिया निजी वाहनों के मामले में भारत अभी शुरूआती चरण में है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत भी उसी निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है, जिसकी चर्चा यूरोप और चीन के संदर्भ में हो रही है?

भारत के सामने इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में बढ़ने का सबसे बड़ा तर्क आर्थिक है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में आयात करता है। तेल की कीमतों में वैश्विक उतार-चढ़ाव सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर महँगाई बढ़ती है, परिवहन लागत बढ़ती है और विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ता है। ऐसे में अगर परिवहन का बड़ा हिस्सा बिजली आधारित हो जाए, तो तेल आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है।

विचार

वर हवाई अड्डे से पहली उड़ान

महेन्द्र तिवारी

उत्तर प्रदेश के विमानन और आर्थिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, जिसे जेवर हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, से पहली व्यावसायिक उड़ान का सफल संचालन शुरू होना न केवल इस राज्य के लिए बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक और लंबे समय से प्रतीक्षित पल है। इस पहली उड़ान के रनवे पर उतरते ही यह विशाल हवाई अड्डा आधिकारिक रूप से वैश्विक विमानन मानचित्र पर स्थापित हो गया है। लंबे समय से देखी जा रही यह महत्वाकांक्षी योजना अब धरातल पर हकीकत बनकर उतर चुकी है, जो आने वाले समय में उत्तर भारत के विकास की दिशा और दशा को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। इस हवाई अड्डे का चालू होना आधुनिक बुनियादी ढांचे, आर्थिक प्रगति और सुदृढ़ कनेक्टिविटी का एक ऐसा अद्भुत संगम है, जो आने वाले कई दशकों तक देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देता रहेगा। उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के विशाल नेटवर्क के साथ एक नए वैश्विक निवेश और आर्थिक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। विमानन उद्योग की दुनिया में कुछ ऐसी अनूठी और भव्य परंपराएं हैं जो इस क्षेत्र के सम्मान और गौरव को प्रदर्शित करती हैं। ऐसी ही एक अत्यंत प्रतिष्ठित वैश्विक परंपरा वॉटर कैनन सैल्यूट की है, जिसके माध्यम से किसी भी नए हवाई अड्डे पर पहली व्यावसायिक उड़ान का ऐतिहासिक स्वागत किया जाता है। जब उत्तर प्रदेश की ही राजधानी लखनऊ से उड़ान भरकर आई इंडिगो एयरलाइंस की पहली उड़ान ने जेवर हवाई अड्डे के नवनिर्मित रनवे पर पहली बार लैंड किया, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए वह दृश्य अत्यंत विहंगम और भावुक करने वाला था। हवाई अड्डे के अग्निशमन दल के वाहनों ने रनवे के दोनों छोरों पर तैनात होकर पानी की तीव्र बौछारें छोड़ीं और हवा में एक अत्यंत सुंदर और विशाल आर्च का निर्माण किया। पानी की इस भव्य बौछार के बीच से गुजरते हुए विमान का स्वागत करना केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक नए और सुनहरे युग के उदय का भव्य शंखनाद था। यह सम्मान और उत्सव का वह क्षण था जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पिछले कई वर्षों से हवाई यात्रियों और उड़ानों के भारी दबाव का सामना कर रहा है। लगातार बढ़ती जनसंख्या और हवाई यात्रा के प्रति आम लोगों के बढ़ते रुझान के कारण दिल्ली हवाई अड्डे की क्षमताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही थीं, जिससे उड़ानों में देरी और भीड़भाड़ जैसी समस्याएं आम हो गई थीं। ऐसे में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू होना दिल्ली हवाई अड्डे के लिए सबसे मजबूत, प्रभावी और आवश्यक विकल्प के रूप में सामने आया है। इसके पूरी तरह चालू होने से दिल्ली हवाई अड्डे पर विमानों के हवाई ट्रैफिक और यात्रियों की लंबी कतारों का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। इसका सबसे सीधा और बड़ा लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और मेरठ के साथ-साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा के कई प्रमुख शहरों के निवासियों को मिलेगा। अब इन क्षेत्रों के लाखों यात्रियों को कोई भी अंतरराष्ट्रीय या घरेलू उड़ान पकड़ने के लिए दिल्ली के भारी ट्रैफिक और जाम से जूझते हुए जाने की मजबूरी नहीं होगी, बल्कि वे सीधे जेवर आकर बेहद कम समय में अपनी सुखद यात्रा शुरू कर सकेंगे। इस हवाई अड्डे के वर्तमान स्वरूप और भविष्य की विशाल योजनाओं का यदि गहराई से विश्लेषण किया जाए, तो इसका मास्टर प्लान अत्यंत विशाल और विस्मयकारी दिखाई देता है। वर्तमान समय में इस हवाई अड्डे के पहले चरण का निर्माण कार्य पूरी तरह संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत 1 रनवे और 1 अत्याधुनिक विशाल टर्मिनल का संचालन शुरू किया गया है। लेकिन यह विशाल परियोजना की केवल एक छोटी सी शुरूआत है। आने वाले वर्षों में जब इसके सभी निर्धारित चरण चरणबद्ध तरीके से पूरे हो जाएंगे, तो यह भारत का सबसे बड़ा और पूरे एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शीर्ष स्थान पर गिना जाएगा।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआई: HPHIN / 2012 / 48072

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन इंडिया कार्यालय, कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना हिमाचल प्रदेश–174303 से प्रकाशित एवं अर्थ प्रकाश प्रैस, अर्थ प्रकाश भवन, सेक्टर–29डी, चंडीगढ़ से मुद्रित।

संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी

समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)

स्थानीय संपादक : पंकज शर्मा (9418026789)

ई–मेल : actionindiashimla@gmail.com
actionindiauna@gmail.com

एक्शन इंडिया शिमला कार्यालय: किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला– 171001

एक्शन इंडिया ऊना कार्यालय: कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना, हिमाचल प्रदेश–174303

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच–पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अत: समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

व्यंग्य

दफनाने और जलाने के बीच

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

मोहल्ले की उस नुक्कड़ वाली दुकान पर आज भी वही फीकी चाय मिल रही थी, जिसे पीकर हम अक्सर अमर प्रेम की कसमें खाया करते थे। फर्क बस इतना था कि आज चाय की प्याली मेरे हाथ में नहीं थी और मैं खुद उस मिट्टी के नीचे था जिसे लोग सुकून की नींद कहते हैं। वैसे, मरना भी एक तरह का स्टार्टअप ही है, बस इसमें रेवेन्यू के नाम पर सिर्फ सिसकियां मिलती हैं। शाम का धुंधलका गहरा रहा था। तभी मुझे अपनी कब्र की छाती पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। मिट्टी की परतों के पार से आती वह महक जानी-पहचानी थी। वही मोगरे वाला इत्र, जो कभी मेरी कमीजों पर अपनी वसीयत लिख दिया करता था। मेरा दिल, जो अब सिर्फ एक खामोश गोश्त का लोथड़ा था, एक पल के लिए धड़कने का नाटक करने लगा। वह आई थी। लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ 'वो' था। वही 'वो', जिसकी सैलरी मेरी कविताओं के छंदों से ज्यादा लंबी थी और जिसकी गाड़ियों के हॉर्न मेरी आवाज से ज्यादा बुलंद थे।

उसे देखकर लगा जैसे नियति ने मेरी मौत पर एक करारा तमाचा जड़ा हो। वह मेरे सिरहाने आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में काजल वैसा ही गहरा था, जैसा उस दिन था जब उसने कहा था, ₹तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी।

मुझे हंसी आई, पर कफन में हंसी के लिए चेहरा नहीं होता।

उसने अपने रेशमी हाथों से मेरी कब्र पर जमी धूल झाड़ी। वह ऐसे सफाई कर रही थी जैसे किसी पुराने अलमारी से फालतू कबाड़ हटाया जा रहा हो। फिर उसने चमेली के फूल चढ़ाए। वही फूल, जिनसे मुझे एलर्जी थी। जीते जी कभी मेरी छींकों की परवाह नहीं की, मरने के बाद भी अपनी पसंद थोप दी। तभी उसके शौहर ने, जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की तरह मैनेज्ड लग रहा था, अपनी कलाई घड़ी देखी। सोने की घड़ी में समय भी शायद महंगा ही बीत रहा होगा।

युद्ध, शांति और सौदेबाजी बीच फँसी दुनिया

डॉ. घनश्याम बादल

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युद्ध और शांति दोनों ही अक्सर आदर्शों से नहीं बल्कि हितों से संचालित होते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी महाशक्ति ने युद्ध छेड़ा है, उसने उसे मानवता, सुरक्षा, लोकतंत्र अथवा विश्व शांति के नाम पर उचित ठहराने का प्रयास किया है, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद जब वास्तविक परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है तो अक्सर सामने आता है कि युद्ध का घोषित उद्देश्य कुछ और था और वास्तविक लक्ष्य कुछ और। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष तथा उसके बाद सामने आई शांति व्यवस्था को भी इसी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि पश्चिम एशिया की सत्ता, संसाधनों, तेल मार्गों, सामरिक वर्चस्व और वैश्विक प्रभाव को लेकर चल रही लंबी खींचतान का नया अध्याय था। अमेरिका और उसके सहयोगी लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। दूसरी ओर ईरान का कहना रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है। इसी विवाद ने समय-समय पर तनाव को जन्म दिया और अंततः स्थिति सैन्य संघर्ष तक पहुँच गई। लेकिन यदि इस पूरे घटनाक्रम को सतह के नीचे जाकर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि परमाणु कार्यक्रम केवल बहाना था, असली संघर्ष पश्चिम एशिया में प्रभाव और नियंत्रण का था। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान क्षेत्रीय शक्ति के रूप में इतना मजबूत हो जाए कि वह उसकी रणनीतिक योजनाओं और इजरायल की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के लिए चुनौती बन जाए।

वहीं ईरान अपने आपको एक स्वतंत्र और प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित रखना चाहता है। युद्ध की शुरूआत जिस आक्रामकता के साथ हुई थी, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को निर्णायक रूप से झुका देंगे। किंतु कुछ ही समय बाद परिस्थितियाँ बदलती दिखाई देने लगीं। युद्ध की आर्थिक लागत लगातार बढ़ रही थी, तेल बाजार अस्थिर हो रहा था।

मप्र कैबिनेटः बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाएं और जन-कल्याण के लिए 24 हजार 200 करोड़ रुपये स्वीकृत

टीम एक्शन इंडिया
भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्रि-परिषद ने राज्य के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण को बड़ी रफ्तार देते हुए कुल 24,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके अलावा, इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण सहित कुल 19,472 करोड़ 29 लाख रुपये का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया गया। राज्य में विश्वस्तरीय सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने और परोपकारी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 'मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति 2026 लागू करने के प्रस्ताव पर मंत्रि-परिषद ने पांच सदस्यीय मंत्रि-मण्डल उप समिति का गठन किया है। साथ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं

को सुदृढ़ करने के लिए रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर चलाने का पायलट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया गया।

इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त 19 हजार 472 करोड़ 29 लाख रुपये मंजूर

प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की मूल लागत 7 हजार 500.80 करोड़ रुपये में 5 हजार 388.58 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत जोड़कर पुनरीक्षित लागत 12 हजार 889.38 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त उद्योग के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण पीपीपी घटक एवं आंतरिक ऋण के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए 6 हजार 582.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस तरह कुल 19 हजार 472 करोड़ 29 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा वन विभाग के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलिफेंट और ग्रामों के पुनर्वास के लिए मुआवजा सम्बंधी योजना के सोलहवें केन्द्रीय वित आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक कुल 5 वर्षों तक संचालन के लिए कुल 2 हजार 381 करोड़ 15 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति के प्रस्ताव पर उपसमिति गठित

मंत्री काश्यप ने बताया कि मंत्रि-परिषद ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा परोपकारी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश (परोपकारी संस्थाओं के लिए) मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को लागू किए जाने के प्रस्ताव पर पांच सदस्यीय मंत्रि-मण्डल उप समिति का गठन किया है।
उप समिति प्रदेश मेंविश्वस्तरीय तृतीयक एवं सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करना, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार विशेषज्ञ व एमबीबीएस डॉक्टर तैयार करना, गरीब मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार की गारंटी, अन्य राज्यों में मरीजों के पलायन को कम करना, स्वास्थ्य संकेत कों एमएमआर और आइएमआर में सुधार करने एवं रोगियों को उन्नत सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने आदि का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने रीवा, देवास तथा गुना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन आउटसोर्स प्रणाली से किए जाने संबंधी पायलट परियोजना संचालित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति का पंजाब दौरा, राज्यपाल से की मुलाकात

दौरा

विधानसभा का भ्रमण कर वहां की लेखा समिति की संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी जुटा रही

टीम एक्शन इंडिया
चित्तौड़गढ़। राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति इन दिनों जम्मू-कश्मीर, पंजाब व हरियाणा के अध्ययन दौरे पर है। समिति इन राज्यों की विधानसभा का भ्रमण कर वहां की लेखा समिति की कार्यप्रणाली और संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी जुटा रही है। दौरे के क्रम में समिति सदस्यों ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित राजभवन में पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद्र कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विभिन्न संसदीय एवं जनहित के मुद्दों पर विस्तार से सार्थक चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभानसिंह आक्या, कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर, बेगूं विधायक सुरेश धाकड़, शार्दूलशहर विधायक गुरवीर सिंह व अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल शामिल रहे। समिति सदस्यों ने पंजाब विधानसभा अध्यक्ष एवं वहां की लेखा समिति के सदस्यों के साथ भी बैठक की। बैठक में लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, सुशासन, जनकल्याण से जुड़े विषयों और संसदीय प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर गहन मंथन हुआ। समिति ने पंजाब विधानसभा की लेखा समिति द्वारा अपनाई जा रही कार्यप्रणाली, वित्तीय अनुशासन और जन लेखा परीक्षण की बारीकियों को समझा। राजस्थान के विधायकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए दोनों राज्यों के बीच संसदीय व्यवस्थाओं को लेकर विचार-विमर्श किया। राज्यपाल गुलाबचंद्र कटारिया ने राजस्थान से आए विधायकों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे अध्ययन दौरे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मददगार होते हैं। जन लेखा समिति की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह समिति सरकारी खर्च पर निगरानी रखकर जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करती है।

भाजपा का विकल्प बनने की क्षमता सिर्फ आप में: संजय सिंह

दावा

आप के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह

टीम एक्शन इंडिया
इंदौर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने और उसके विकल्प के रूप में उभरने की क्षमता केवल आप पार्टी में है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करती है, जबकि आप पार्टी जनता के मूलभूत मुद्दों जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर काम करती है। संजय सिंह सोमवार शाम को इंदौर के आनंद मोहन माथुर सभागृह में आयोजित आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं पदग्रहण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरूआत मां सरस्वती, शहीद भगत सिंह और डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। पार्टी के कार्यकर्ता देश के हर क्षेत्र में है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता के हितों की बजाय बड़े उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही उन्होंने विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

रायपुरः शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश हमारी प्राथमिकताः मुख्यमंत्री साय

टीम एक्शन इंडिया
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आज मंगलवार को दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर स्वामी राजीव लोचन दास महाराज, निवार्णी अखाड़ा के महंत सुरेंद्र दास महाराज, शदाणी दरबार से उदय लाल तथा कबीर आश्रम सोनपैरी के देवकर साहब ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर संत-महात्माओं ने छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों एवं नैतिक शिक्षा से जुड़े पारंपरिक श्लोकों और मंत्रों को पुनः शामिल किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री साय के

प्रति आभार व्यक्त किया। संतों ने कहा कि पूर्व में विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर जैसे मंत्रों एवं भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित कराया जाता था, जिससे बच्चों में संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होता था।

चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विभिन्न संत-महात्माओं ने की सौजन्य भेंट, कई विषयों पर हुई चर्चा

समय के साथ ये परंपराएं शैक्षणिक वातावरण से धीरे-धीरे विलुप्त होती गईं, किंतु अब राज्य सरकार द्वारा इन्हें पुनः स्थापित करने की पहल अत्यंत स्वागतयोग्य है। संत समाज ने कहा कि विद्यालयों में शांतिपाठ, सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र तथा अन्य प्रेरणादायी वैदिक एवं सांस्कृतिक प्रार्थनाओं का समावेश बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे नई पीढ़ी भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जुड़ सकेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कार, चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों के विकास का आधार भी है। हमारी सरकार बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालयों में शांतिपाठ, सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र एवं अन्य प्रेरणादायी प्रार्थनाओं के समावेश से विद्यार्थियों में अनुशासन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना का विकास होगा। यह पहल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए एक संस्कारित, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संत-महात्माओं ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को इस पहल के लिए साधुवाद देते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया तथा कहा कि यह निर्णय प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक विरासत को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

दिवंगत निविदा कार्मिक के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग

टीम एक्शन इंडिया
जोधपुर। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के अध्यक्ष जगदीश जाट के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में जयपुर में कार्यरत निविदा कार्मिक नर्सिंग अधिकारी स्वर्गीय दीपक खारवाल की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की गई। संगठन ने मांग की है कि स्वर्गीय दीपक खारवाल के परिजनों द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई समस्त मांगों, जिनमें उचित आर्थिक मुआवजा, परिवार के पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी एवं अन्य सहायता शामिल हैं, को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए।
संगठन ने यह भी मांग रखी है कि प्रदेश में सेवा से पृथक किए गए अथवा रोजगार से वंचित हुए सभी निविदा एवं संविदा नर्सिंग कार्मिकों के लिए उचित समायोजन एवं पुनर्नियोजन की व्यवस्था की जाए, ताकि उनके रोजगार एवं आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

शुभेंदु की घोषणाएं: 125 दिन रोजगार, पुलिस भर्ती और पहाड़ के विकास का वादा

रोजगार पर बल

भाजपा) लंबे समय से पहाड़ की साथी रही है और उनकी उम्मीदों को पूरा किया जाएगा।

टीम एक्शन इंडिया
कर्सियांग। कर्सियांग में आयोजित एक सभा में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहाड़ के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने पहाड़ के लोगों के साथ अपने पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लंबे समय से पहाड़ की साथी रही है और उनकी उम्मीदों को पूरा किया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक जुलाई से पहाड़ के निवासियों को 125 दिनों के रोजगार का लाभ मिलेगा। रोजगार के मुद्दे पर भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि अब शिक्षक भर्ती में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और जल्द ही पुलिस में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे पहाड़ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि पहाड़ी क्षेत्रों की सभी महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना का लाभ दिया जाएगा। जनजातीय समुदाय के लोगों को राशन में विशेष सब्सिडी और बिजली बिल में छूट भी दी जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में साढ़े छह करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। पहले राज्य में नकारात्मक सोच वाली सरकार थी, लेकिन अब उनका उद्देश्य केवल काम करना और पहाड़ का विकास करना है।

सीएम तथा समूची कैबिनेट को अकाल तख्त के तलब करने पर पंजाब की राजनीति गरमाई

टीम एक्शन इंडिया
चंडीगढ़। अकाल तख्त साहिब की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री तथा समूची कैबिनेट को तलब किए जाने के बाद पंजाब की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को उनके नाम से जोड़े जा रहे एक वीडियो को सिरे से नकारते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल के इशारे पर उन्हें बदनाम करने और उनकी सरकार के लोक-हितैषी फैसलों से ध्यान हटाने के लिए घृणित हरकत और राजनीतिक साजिश रची जा रही है। इस घटना को सरकार के सख्त बेअदबी विरोधी कानून और पंजाब-पक्षी फैसलों से घबराकर की गई बौखलाहट भरी कोशिश बताते हुए

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा प्रचार करने के लिए राजनीतिक प्रभाव के अधीन काम कर रहे अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि वे श्री अकाल तख्त साहिब को सर्वोच्च मानते हैं और सम्मान के साथ इसकी आस्था के आगे पूरी नम्रता से सिर झुकाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिशों की परवाह किए बिना वे पंजाब के पानी, जवानी, किसानी और बाणी के हित में दलेराना फैसले लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान खुलेआम अकाली दल के प्रचारक बन गए हैं। अब तो

मचा बवाल

पंजाब के पानी, जवानी, किसानी और बाणी की रक्षा के लिए मेरी सरकार के फैसलों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे

सिर्फ यही कसर बाकी रह गई है कि जत्थेदार साहिब के जरिए यह फरमान जारी करवा दिया जाए कि सुखबीर बादल को वोट दो, नहीं तो पंथ खतरे में है। ऐसा फैसला किसी भी वक्त लिया जा सकता है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दुनिया भर के पंजाबियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने जत्थेदार साहिब के सामने साफ कर दिया था कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वीडियो में दिखाए गए व्यक्ति की न तो शारीरिक बनावट और न ही चेहरा मेरे साथ मेल खाता है, फिर भी मेरे अक्स को खराब करने के लिए झूठा और गुमराहपूर्ण प्रचार किया जा रहा है।
इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि इतनी ऊंची धार्मिक पदवियों पर बैठे लोग खुद को राजनीतिक एजेंडे और झूठे प्रचार का हथियार बना रहे हैं। कुछ लोग पंजाब के पानी, जवानी, किसानी और बाणी की रक्षा के लिए मेरी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।

दूसरे दलों ने ओबीसी समाज का चुनावी स्वार्थ के लिए किया उपयोगः मायावती

टीम एक्शन इंडिया
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को पार्टी की बैठक की। बैठक के बाद जारी
एक बयान में मायावती को आयरन लेडी बताते हुए बसपा ने अन्य दलों पर राजनीति स्वार्थ के लिए पिछड़ा वर्ग (ओबीसी समाज) के उपयोग करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी समाज) का हित और

कल्याण बसपा की आयरन लेडी सरकार में ही निहित है जबकि अन्य दूसरी पार्टी में नहीं है। विरोधी पार्टियों के भीतर व उनकी सरकारों में भी राजनीतिकि और चुनावी स्वार्थ के तहत व्यकितगत तौर पर किसी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ओबीसी समाज की राजनितिक, आर्थिक विकास और उन्नति के लिए इन पार्टियों का रवैया ज्यादातार संकीर्ण रहा है। उन्होंने शिक्षा और नौकरियों में मिलने वाली 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को कमजोर करने का मुद्दा उठाया है। जबकि बसपा की सरकार में ओबीसी समाज को भागीदारी दी थी। साथ ही पूरे आत्मसम्मान के साथ जीने हक दिया गया। उन्होंने कहा कि बसपा ने सदियों से यहां उपेक्षित समाज के महापुरुषों को पूरा सम्मान देकर सामाजिक परिवर्तन और अर्थिक मुक्ति को मजबूत आधार देने का प्रयास किया।

विज्ञान आधारित पशुधन विकास से ग्रामीण आत्मनिर्भरता को मिलेगा बल : राज्यपाल

टीम एक्शन इंडिया
नैनीताल। उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) मुक्तेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए ह्यखेत बचाओ अभियानह्व का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान और अनुसंधान का वास्तविक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण समुदायों तक पहुंचना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आईवीआरआई मुक्तेश्वर विज्ञान, सेवा और राष्ट्रनिर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसने पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, जैव सुरक्षा और पशुधन विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और विशेष रूप से महिलाओं की आजीविका तथा आत्मनिर्भरता का प्रमुख आधार है। उन्होंने वैज्ञानिकों से ह्यलैब टू लैंडह्व की अवधारणा को और अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान करते हुए अनुसंधान का लाभ दूरस्थ गांवों और सीमांत

पशुपालकों तक पहुंचाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि विज्ञान आधारित डेयरी, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन तथा अन्य पशुधन आधारित गतिविधियों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर युवाओं के लिए स्वरोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जा सकते हैं। उन्होंने संस्थान से युवाओं को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में विशेष पहल करने का आग्रह किया। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने ह्यवन हेल्थह्व अवधारणा को समय की आवश्यकता बताते हुए मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच समन्वित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। उन्होंने बद्री गाय सहित उत्तराखंड की स्वदेशी पशु नस्लों और स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता रेखांकित की तथा प्राकृतिक खेती और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के वैज्ञानिक प्रमाणीकरण पर जोर दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टेली-वेटरिनरी सेवाओं और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के पशुपालकों तक विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने की संभावनाओं का भी उल्लेख किया। युवा वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों से गांवों में जाकर किसानों व पशुपालकों की समस्याओं को समझने तथा उनके व्यावहारिक समाधान विकसित करने का आह्वान करते हुए उन्होंने संस्थान से आगामी वर्षों में उत्तराखंड में कम से कम 100 मॉडल पशुपालक गांव विकसित करने की दिशा में कार्य करने को कहा। कार्यक्रम से पूर्व राज्यपाल ने संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और प्राकृतिक कोल्ड स्टोरेज कक्ष का भ्रमण किया। इस अवसर पर निदेशक डॉ. राघवेंद्र भट्टा, संयुक्त निदेशक डॉ. एसके सिंह, डॉ. शेर सिंह सहित संस्थान के अधिकारी और कृषक उपस्थित रहे।

प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया गेस्ट हाउस व अटल कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास

टीम एक्शन इंडिया
हाथरस। उत्तर प्रदेश हाथरस,उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री एवं जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने मंगलवार को ग्राम हतीसा भगवन्तपुर में प्रस्तावित अटल कन्वेंशन सेंटर एवं गेस्ट हाउस निर्माण परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा गार्ड ऑफ ऑनर द्वारा उन्हें सलामी दी गई। अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में बनने वाले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि, सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर, सिकंदराराऊ विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह, मुख्य विकास अधिकारी पी.एन. दीक्षित सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि लगभग 200 लोगों की क्षमता वाला आधुनिक अटल कन्वेंशन सेंटर जनपदवासियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। यहां सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा।

हिमाचल न्यूज़
एक्शन इंडिया

www.actionindialive.com

ऊना,
17 जून 2026

राज्यपाल ने फतेहपुर में श्री सर्व धर्म पीठ के तपोस्थान मुख्य दरबार साहिब का लोकार्पण किया

विरासत

» यह स्थान भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का एक जीवंत उदाहरण

विजय समयाल

कांगड़ा। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज कांगड़ा जिला के फतेहपुर में श्री सर्व धर्म पीठ तपोस्थान, गुरुद्वारा श्री नानक ज्योत साहिब में नव-निर्मित मुख्य दरबार साहिब का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने श्रद्धालुओं, संतों, सेवादारों और अतिथियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह स्थान भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत, सांस्कृतिक समावेशिता और सद्भाव का एक जीवंत उदाहरण है जो सर्व धर्म समभाव की भावना को बढ़ाता है। इस स्थान के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुप्ता ने कहा कि मान्यता के अनुसार गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के दौरान इस स्थान पर रहे थे। यहां मिली प्राचीन कृतियां, पुराने नागनी माता मंदिर और पवित्र बरगद के वृक्ष इस बात का प्रमाण हैं कि यह क्षेत्र लंबे समय से तपस्या और साधना का केंद्र रहा है।

गुरु नानक देव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि समानता, करुणा, सेवा भाव और सत्य की उनकी शिक्षाएं वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिक हैं और लोगों को मिल-जुलकर रहने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने मुख्य सेवादार संत बाबा श्री लवप्रीत जी महाराज के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस पवित्र स्थल को सर्व धर्म पीठ के रूप में विकसित करने की उनकी परिकल्पना भारत की प्राचीन समावेशी, सह-अस्तित्व और आध्यात्मिक सद्भाव की परंपरा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि एक ही परिसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना, मंदिर तथा अखंड ज्योति का होना सच्ची आध्यात्मिकता का प्रतीक है।

बल्क ड्रग पार्क का विरोध करने वाले आज श्रेय लेने में जुटे: राम कुमार

राजन पुरी

ऊना। भाजपा नेता प्रो. राम कुमार ने आरोप लगाया है कि बल्क ड्रग पार्क परियोजना का विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता वास्तव में कांग्रेस समर्थित लोग थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में जब भाजपा सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हिमाचल प्रदेश लाने के लिए प्रयासरत थी, तब कांग्रेस से जुड़े लोगों ने प्रशासन के समक्ष इसका विरोध दर्ज करवाया था।

मंगलवार को ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रो. राम कुमार ने कहा कि उस समय परियोजना के खिलाफ पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का मुद्दा उठाया गया। लाखों पेड़ों के कटान और क्षेत्र में रहने वाले भालुओं के विस्थापन जैसी दलीलें देकर इस महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजना को रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के समर्थक भी उस विरोध का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को शुरुआत में यह परियोजना केवल एक राजनीतिक घोषणा लगती थी, लेकिन केंद्र सरकार से धनराशि स्वीकृत होने और परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद उनका रुख पूरी तरह बदल गया। आज वही लोग इस परियोजना का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बड़े निवेश आएंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रो. रामकुमार ने एक अन्य मुद्दा उठाते हुए कहा कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बल्क ड्रग पार्क परियोजना का शिलान्यास किया गया था, लेकिन आज तक परियोजना स्थल पर प्रधानमंत्री के नाम की आधिकारिक शिलान्यास पट्टिका स्थापित नहीं की गई है।

व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट! पुराने बस स्टैंड पर बनेगा मॉडर्न सिटी सेंटर

नोटिस

» दुकानदारों को 72 घंटे के भीतर दुकानें खाली करने का जारी किया नोटिस

पवन धीमान

हमीरपुर। हमीरपुर शहर के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इस बदलाव की कीमत पुराने बस स्टैंड परिसर में वर्षों से कारोबार कर रहे करीब डेढ़ दर्जन व्यापारियों को चुकानी पड़ सकती है। प्रशासन ने पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में प्रस्तावित आधुनिक सिटी सेंटर परियोजना को गति देने के लिए दुकानदारों को मात्र 72 घंटे के भीतर दुकानें खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। इस फैसले ने प्रभावित व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने पहले व्यापारियों को दुकानें खाली करने के लिए 14 दिन का समय दिया था, लेकिन अब जारी नए नोटिस में यह अवधि घटाकर केवल तीन दिन कर दी गई है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि तय समयसीमा के भीतर परिसर खाली नहीं करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुराना बस स्टैंड परिसर नगर निगम को हस्तांतरित किए जाने के बाद यह कार्रवाई तेज हुई है। प्रशासन का कहना है कि भूमि अब नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है और सिटी सेंटर निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाना है। परियोजना के तहत क्षेत्र में स्थापित पुराने ट्रांसफार्मर को भी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दुकानदारों की सबसे बड़ी चिंता उनके भविष्य को लेकर है। व्यापारियों का कहना है कि 33 महीने के अनुबंध के आधार पर आवंटित दुकानों की डीड निरस्त कर दी गई है और अब उन्हें अचानक दुकानें खाली करने को कहा जा रहा है।

ट्रिपल आईटी में पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित

राजन पुरी

ऊना। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पूर्णकालिक और अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान में एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर एवं वीएलएसआई डिजाइन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, उन्नत संचार प्रणालियां, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और सामरिक सेंसिंग प्रणालियों जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में शोध करने का अवसर मिलेगा। संस्थान के अनुसार यह कार्यक्रम सहयोगात्मक, अंतर्विषयक और उद्योग व समाज की आवश्यकताओं पर आधारित शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा केन्द्र में हिमाचल के हितों की पैरवी करने में रहे असफल : नरेश चौहान

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा केन्द्र में हिमाचल के हितों की पैरवी करने में असफल रहे हैं। हाल ही में हिमाचल के प्रवास पर आए जे.पी. नड्डा ने हिमाचल से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने पिछली भाजपा सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने का काम किया।

आरडीजी बन्द करने के निर्णण को न्यायसंगत करार देना यह साबित करता है कि उन्होंने प्रदेश के हितों से समझौता कर लिया है। उनको यह ज्ञात होना चाहिए कि इस पहाड़ी राज्य के गठन के समय भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य की राजस्व की कमी की भरपाई के लिए आरडीजी का प्रावधान किया गया था। आरडीजी हिमाचल प्रदेश का संवैधानिक अधिकार है, कोई खैरात नहीं। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275(1) में किया गया है और इसे बन्द करना हिमाचल के लोगों के अधिकारों के साथ कुठाराघात है।

उन्होंने कहा कि जे.पी. नड्डा केन्द्र में प्रभावशाली स्थान रखते हैं। उन्हें प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए प्रदेश सरकार और विपक्ष को साथ लेकर बैठक करनी चाहिए थीं और इस मामले को प्रभावशाली तरीके से केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था लेकिन यह आर्श्चजनक है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजनीतिक दृष्टि से आरडीजी बन्द होने को न्यायसंगत बता रहे हैं। यह सरासर प्रदेश के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ है क्योंकि आरडीजी बंद होने से प्रदेश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को आरडीजी के रूप में हज़ारों करोड़ रुपये तथा जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में 16 हज़ार करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इस सबके बावजूद पूर्व सरकार ने हिमाचल पर भारी भरकम कर्ज़ के बोझ तले दबा दिया। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से सवाल पूछने चाहिए कि उन्होंने पांच वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए थे।

डाक जीवन बीमा की किस्तों में गड़बड़ी, सब-पोस्टमास्टर पर सीबीआई ने दर्ज किया मामला

हामिद खान

चंबा। जिला चंबा के सुल्तानपुर उप-डाकघर में डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) की प्रीमियम राशि में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की शिमला स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एक तत्कालीन सब-पोस्टमास्टर के खिलाफ सरकारी धन के गबन और भ्रष्टाचार से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार आरोपी कर्मचारी ने अपने कार्यकाल के दौरान बीमा धारकों से प्रीमियम और ऋण अदायगी की राशि नकद रूप में प्राप्त की। आरोप है कि ग्राहकों की पॉलिसियों में प्रीमियम जमा होने की प्रविष्टियां तो कर दी गईं, लेकिन संबंधित राशि को सरकारी लेखा प्रणाली में पूर्ण रूप से जमा नहीं कराया गया। कुछ मामलों में राशि दर्ज ही नहीं की गई, जबकि कुछ में कम दर्ज किए जाने के आरोप हैं।

यह मामला चंबा मंडल के डाक अधीक्षक राजीव गुरंग की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। जांच में पाया गया कि नवंबर 2018 से अप्रैल 2022 के बीच हुई लेन-देन में अनियमितताएं बरती गईं। प्रारंभिक जांच के दौरान मार्च 2019 से सितंबर 2021 के बीच 1.06 लाख रुपये से अधिक की सरकारी राशि के गबन की पुष्टि होने का दावा किया गया है।

सीबीआई का आरोप है कि सरकारी धन का उपयोग निजी लाभ के लिए किया गया, जिससे सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचा। मामले की विस्तृत जांच जारी है और एजेंसी अन्य लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है।

संक्षिप्त खबरें

अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2026 की व्यवस्थाओं से संबंधित कार्य प्रगति वारे समीक्षा बैठक आयोजित

हामिद खान

चंबा। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला-2026 की व्यवस्थाओं से संबंधित कार्य प्रगति वारे जिला मुख्यालय चंबा के बचत भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। बैठक में मेले के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मिंजर मेले के दौरान होने वाले व्यय व आय, निमंत्रण कार्ड /स्मारिका, परिवहन, यातायात व पार्किंग प्रबंधन, खेलकूद प्रतियोगिताओं, चौगान रखरखाव, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति के अतिरिक्त साफ-सफाई तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था के सहित कला केन्द्र व मंजरी गार्डन में आवश्यक मुरम्मत के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिला चंबा का सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक तथा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिंजर मेला देश विदेश में जिला चंबा की पहचान व शान का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त मिंजर मेला जिला चंबा की प्राचीन समृद्ध संस्कृति तथा समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी मेल मिलाप व आपसी भाईचारे का भी प्रतीक है।

एआर मेंटर ग्रुप एवं जीजी परामर्श संस्था के निदेशक अरुणेश ठाकुर की यूलिया कासियुना से शिष्टाचार भेंट

कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। एआर मेंटर ग्रुप एवं जीजी परामर्श संस्था के निदेशक अरुणेश ठाकुर ने आज रूस के सरकारी विश्वविद्यालयों के अंतरराष्ट्रीय विभाग की प्रमुख यूलिया कासियुना से एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान भारतीय विद्यार्थियों के लिए रूस में उच्च शिक्षा के अवसरों, मार्गदर्शन तथा सहयोग को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तराखंड से रूस के सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने की जिम्मेदारी पर सहमति बनी। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया, विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, छात्रवृत्ति के अवसरों तथा अध्ययन से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर अरुणेश ठाकुर ने कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय विभाग की प्रमुख यूलिया कासियुना का आभार व्यक्त करते हैं।

गैर पंजीकृत रिक्शा पर कार्रवाई की मांग, पंजीकृत चालकों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन

राजन पुरी

ऊना। जिला मुख्यालय ऊना में गैर पंजीकृत ऑटो रिक्शा के संचालन को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। पंजीकृत ऑटो रिक्शा संचालकों ने आरोप लगाया है कि बाहरी क्षेत्रों से आकर बिना वैध पंजीकरण और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए कुछ लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, जिससे न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि नियमों का पालन करने वाले चालकों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है।

इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को पंजीकृत ऑटो रिक्शा चालकों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए तो वे अपने ऑटो रिक्शा प्रशासनिक परिसर में खड़े कर उनकी चाबियां अधिकारियों को सौंपने के लिए मजबूर होंगे।

प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे महेंद्र सैनी और सतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने सभी सरकारी नियमों और औपचारिकताओं को पूरा करते हुए ऑटो रिक्शा खरीदे हैं तथा नियमित रूप से कर एवं अन्य शुल्क जमा करते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई गैर पंजीकृत ऑटो रिक्शा चालक कम किराए पर सवारियां बैठाकर न केवल पंजीकृत ऑटो चालकों बल्कि बस ऑपरेटरों को भी आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं।

इसके चलते वैध रूप से काम कर रहे चालकों की आय लगातार घट रही है और उनके लिए बैंक ग ण की किस्तें चुकाना भी कठिन होता जा रहा है।

दौलतपुर चौक कॉलेज में बीबीए-बीसीए की मेरिट सूची जारी

राजन पुरी

ऊना। राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय दौलतपुर चौक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीबीए एवं बीसीए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। महाविद्यालय प्रशासन के अनुसार चयनित विद्यार्थी 17 जून तक अपने सभी मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश सुनिश्चित करें। प्राचार्य डॉ. अजय शर्मा ने विद्यार्थियों से निर्धारित समय के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में बीए, बीएससी एवं बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है। इ%छुक विद्यार्थी निर्धारित तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

पेट्रोल पंप डीलरों ने कहा- नियम मानना मजबूरी, आने वाले दिनों में और कड़े होंगे कानून

पवन धीमान

हमीरपुर। देशभर में डीजल वितरण व्यवस्था को लेकर सरकार के नए नियमों ने ट्रांसपोर्टरों, ठेकेदारों और बड़े उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों की ओर से लागू किए जा रहे नए प्रावधानों के तहत अब रिटेल पेट्रोल पंपों से 200 लीटर से अधिक डीजल देने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ड्रम, कैन और अन्य अनाधिकृत पात्रों में डीजल बिक्री पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि वे केवल सरकारी आदेशों और कानूनों के तहत काम कर रहे हैं तथा नियमों की अवहेलना करने की स्थिति में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

जानकारी के अनुसार सरकार ने डीजल उपभोक्ताओं को दो श्रेणियों—रिटेल और कंज्यूमर—में विभाजित किया है। रिटेल श्रेणी में आम वाहन चालक शामिल हैं, जबकि बड़ी निर्माण कंपनियां, रेलवे, एचआरटीसी और बड़े ठेकेदारों को कंज्यूमर श्रेणी में रखा गया है। ऐसे संस्थानों को अलग व्यवस्था के तहत ईंधन उपलब्ध करवाने की योजना बनाई गई है।

सूत्रों के अनुसार सरकार बड़े उपभोक्ताओं और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए अलग मूल्य निर्धारण प्रणाली पर काम कर रही है, जबकि आम जनता के लिए डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश की जा रही है। इसी कारण रिटेल और कंज्यूमर श्रेणी के बीच मूल्य अंतर को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

पेट्रोल पंप डीलरों का कहना है कि नए नियमों के कारण उनकी बिक्री और कारोबार प्रभावित हो रहा है, लेकिन मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है।

डीलरों ने साफ किया कि इन नियमों को बदलने का अधिकार स्थानीय प्रशासन, डीसी या राज्य सरकार के अधिकारियों के पास नहीं है, क्योंकि यह सीधे केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय का नीतिगत फैसला है।

जिला में 10वीं राज्य स्तरीय मेगा आपदा मॉक ड्रिल आयोजित

हामिद खान

चंबा। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला चंबा में 10वीं राज्य स्तरीय मेगा आपदा मॉक ड्रिल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

इस अभ्यास का उद्देश्य भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने तथा सड़क दुर्घटना जैसी संभावित आपदाओं के दौरान विभिन्न विभागों एवं आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों की तत्परता, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना था।

मॉक ड्रिल के अंतर्गत प्रातः 9 बजे रिक्टर पैमाने पर 8.0 तीव्रता के भूकंप की काल्पनिक स्थिति तैयार की गई। इसके परिणामस्वरूप जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भवनों के क्षतिग्रस्त होने, भूस्खलन, बादल फटने तथा बस दुर्घटना जैसी आपात परिस्थितियों के परिदृश्य निर्मित किए गए। तत्पश्चात जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को सक्रिय करते हुए सभी संबंधित विभागों एवं एजेंसियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किए गए।

घर पर खड़ी गाड़ी का टोल प्लाजा पर कटा फास्टैग शुल्क बरमाना निवासी सुरेश चंद ने उठाए सवाल

कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। बरमाना सीमेंट नगरी निवासी सुरेश चंद के साथ एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है जिसमें उनकी गाड़ी घर पर खड़ी होने के बावजूद टोल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से पैसे कट गए।

सुरेश चंद ने बताया कि उनकी गाड़ी नंबर ।।क्क 69 ॣ 1501 है। सोमवार 15 जून 2026 को सुबह करीब 4ः44 बजे उनके मोबाइल पर एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें जानकारी दी गई कि उनकी गाड़ी का ग्रामौड़ा टोल प्लाजा पर शुल्क कट गया है। जबकि उस समय उनकी गाड़ी घर पर ही खड़ी थी और कहीं भी बाहर नहीं गई थी।

उन्होंने हैरानी जताते हुए बताया कि उनके अकाउंट से 320 रुपए की राशि काट ली गई जबकि सामान्य तौर पर कार का टोल शुल्क इतना नहीं होता है। इस घटना के बाद सुरेश चंद ने आशंका जताई है कि कहीं उनके फास्टैग का गलत इस्तेमाल या कोई तकनीकी गड़बड़ी तो नहीं हुई है। उन्होंने संबंधित विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक संदीप धवल को भी शिकायत दी जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र के अन्य वाहन चालकों में भी चिंता का माहौल है और लोग अपने फास्टैग लेनदेन को लेकर सतर्क हो गए हैं।

हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी

राजन पुरी

ऊना। हिमोत्कर्ष राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द में बीए, बीकॉम, बीबीए व बीसीए में प्रवेश प्रक्रिया जारी है।

इच्छुक छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकती हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द के कार्यवाहक प्राचार्य डा. रमन जसवाल ने बताया कि महाविद्यालय में बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सहित चार संकाय चलते हैं। इनमें छात्राएं अपना उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए प्रवेश ले सकती हैं।

उन्होंने सभी अभिभावकों तथा विद्यार्थियों से आग्रह कि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर व अप्लाई करें।

सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस सरकार जनता पर डाल रही अतिरिक्त बोझ : जय सिंह

हामिद खान

चंबा। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जय सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है और चुनावी वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है।

जय सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं आज भी इस राशि का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि केवल चंबा जिले में ही करीब 21 हजार महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिला है, जबकि प्रदेशभर में लाखों महिलाएं भुगतान की प्रतीक्षा कर रही हैं।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि डेढ़ सप्ताह के भीतर पात्र महिलाओं के खातों में योजना की राशि जारी नहीं की जाती है तो भाजपा व प्रभावित महिलाओं के साथ चंबा स्थित सीडीपीओ कार्यालय के बाहर ताला लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे।

भाजपा नेता ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार देने के नाम पर भी सरकार ने केवल आश्वासन दिए हैं, जबकि लाखों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं।

परिवहन व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। जय सिंह ने कहा कि जिला चंबा की सड़कों पर आए दिन निगम की बसों में तकनीकी खराबी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने निगम प्रबंधन से मांग की कि बसों को रूट पर भेजने से पहले उनकी नियमित जांच, मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की भी अनदेखी कर रही है। महंगाई भत्ता (डीए) सहित अन्य वित्तीय लाभ लंबित पड़े हैं, जिसके चलते पेंशनरों को विरोध-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।